वर्ष 13 • अंक 21 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 12 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

एथनॉल खरीद के लिए नई निविदा जारी

अमित शाह पृष्ठ 14

दिल्ली हिंसा सुनियोजित साजिश : शाह

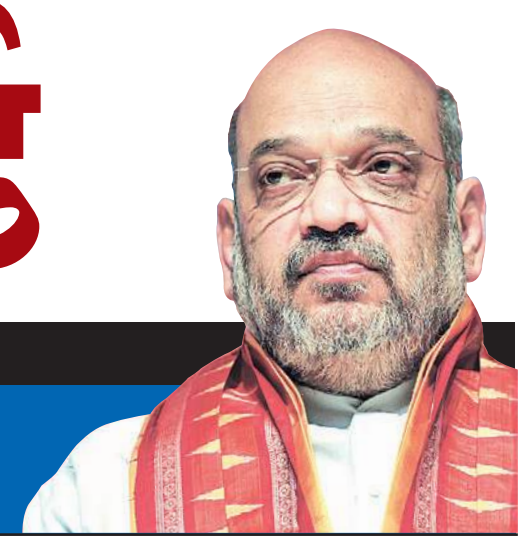

डॉलर रु. 73.60 ▼ 50 पैसे | यूरो रु. 83.50 ▼ 01.10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 43473 ▼ 365 रुपये | सेंसेक्स 35697.40 ▲ 62.40 | निफ्टी 10458.40 ▲ 07.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 10450.80 ▼ 07.70 | ब्रेंट क्रूड 34.90 डॉलर ▼ 01.70 डॉलर

एक नज़र

भाजपा में शामिल सिंधिया संकट में कमलनाथ सरकार

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में सिंधिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए वह लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे। सिंधिया ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। सिंधिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। पृष्ठ 14

मोबाइल फोन और कपड़े पर बढ़ेगी जीएसटी दर

मोबाइल फोन, जूते-चप्पल, वस्त्र एवं उर्वरकों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं पर कर बढ़ाया जा सकता है। इन वस्तुओं के अलावा हरेक महीने 1 करोड़ रुपये पुरस्कार वाली मासिक लॉटरी योजना भी जीएसटी परिषद के समक्ष चर्चा के लिए रखी जा सकती है। इसका मकसद खरीदारों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पृष्ठ 4

टाटा पावर ने मुंद्रा को बंद करने का फैसला टाला

निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने अपना मुंद्रा पावर प्लांट बंद करने का फैसला 9 दिन के लिए टाल दिया है। इस संयंत्र से बिजली खरीदने वाले पांच राज्यों को भेजे गए पहले के नोटिस में कंपनी ने गुजरात स्थित इस बिजली संयंत्र को बुधवार से बंद करने की सूचना दी थी। अब कंपनी 20 मार्च तक सामान्य परिचालन जारी रखेगी। मुंद्रा के 4,000 मेगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र से से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को बिजली की आपूर्ति होती है। पृष्ठ 4

एयरटेल ने 13,000 करोड़ रुपये का किया भुगतान!

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बुधवार को दावा किया कि कंपनी ने करीब 13,000 करोड़ रुपये के सांविधिक बकाया का भुगतान कर दिया है। सरकार ने 4 मार्च को भारती, वोडाफोन आइडिया तथा अन्य दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय बकाया मद में बची शेष राशि का भुगतान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार बिना किसी विलंब के करने को कहा था।

बैंक के शीर्ष प्रबंधन पर गिरेगी गाज!

आरबीआई कर रहा येस बैंक के शीर्ष अधिकारियों से ईसॉप्स और बोनस वापस लेने पर विचार

रघु मोहन
मुंबई, 11 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) येस बैंक के शीर्ष प्रबंधन के सभी अधिकारियों को अब तक जारी किए गए ईसॉप्स और बोनस को वापस लेने पर विचार कर रहा है। खस्ताहाल येस बैंक के शीर्ष प्रबंधन के वर्गीकरण को भी देखा जा रहा है क्योंकि इस श्रेणी में 100 से अधिक लोग हैं, जिनकी संख्या बड़े निजी बैंकों की तुलना में काफी ज्यादा है। यही नहीं, इनकी संख्या दर-दर-साल तेजी से घटती-बढ़ती रही है।

यह अपनी तरह का पहला मौका होगा जब बैंकिंग नियामक पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य कार्याधिकारियों, मैटीरियल रिस्क टेकर्स और बैंक के परिचालन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के मुआवजे पर 4 नवंबर, 2019 के दिशानिर्देश का इस्तेमाल करेगा। येस बैंक के मामले में इसके दायरे में बैंक के अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ अध्यक्ष, समूह अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समूह अध्यक्ष तक आएंगे। सभी के नजरें इस महीने के अंत में होने वाली आरबीआई के वित्तीय पर्यवेक्षण की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है। येस बैंक के घटनाक्रम के बाद आरबीआई बोर्ड की यह पहली बैठक हो रही है। आरबीआई ने 4 नवंबर के अपने परिपत्र में कहा था कि यह 1 अप्रैल, 2020 से केवल वेतन चक्र पर लागू होगा, लेकिन यह अन्य लाभों को वापस लेने का भी काम कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त परिपत्र को 13 जनवरी, 2012 को जारी दिशानिर्देश के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

आरबीआई के नवंबर 2019 और इससे पहले 2012 की अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि ईसॉप्स, बोनस या अन्य लाभों को वापस लेना केवल प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पर ही लागू होगा, जैसा कि 2018 में आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोछड़ के मामले में हुआ था।

मुआवजे पर नवंबर 2019 के संशोधित नियमों का मकसद उनके फाइनैंशियल स्टैबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) के मार्च 2018 के दिशानिर्देशों के अनुकूल बनाना था।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- येस बैंक के **30,000** करोड़ रुपये के फंसे कर्ज में कपूर की भूमिका जांच रहा ईडी
- धनशोधन से जुड़े मामले की जांच कर रहा ईडी
- देश-विदेश में चिह्नित संपत्तियों की सूची बना रहा ईडी

येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को मंगलवार को मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 16 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

फंसे कर्ज में कपूर की भूमिका की जांच

श्रीमी चौधरी और सुब्रत पांडा
नई दिल्ली, 11 मार्च

येस बैंक के 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा फंसे कर्ज प्रवर्तन निदेशालय के जांच के घेरे में है। बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की मांग करते हुए जांच एजेंसी ने सत्र न्यायालय से कहा कि निदेशालय इसकी जांच कर रहा है कि क्या कंपनियों को आवंटित इन कर्जों का धनशोधन कपूर के नियंत्रण वाली 78 इकाइयों को किया गया।

पीएमएलए की विशेष अदालत ने राणा कपूर की हिरासत की अवधि बढ़ाकर 16 मार्च कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सौंपे रिमांड आवेदन में कहा, पाया गया कि येस बैंक की तरफ से कपूर के कार्यकाल में कई कंपनियों को दिए गए 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज गैर-निष्पादित आस्तियों में बदल गए। यह तय करने के लिए कपूर से पूछताछ की जरूरत है कि क्या कर्ज के रूप में दी गई इस रकम का धनशोधन तो नहीं किया गया। निदेशालय ने यह भी कहा कि 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज की जांच अनियमितता, रिश्वत आदि के नजरिये से हो रही है। ईडी की जांच में पाया गया कि कपूर परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली करीब 78 कंपनियां हैं, जिनका नियंत्रण व प्रबंधन कपूर करते हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एसबीआई ने न्यूनतम बैलेंस की पाबंदी हटाई

अभिजित लेले
मुंबई, 11 मार्च

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ब्याज दर में बड़ा संशोधन किया है। बैंक अब अपने बचत खाताधारकों को उनकी जमा रकम पर सालाना 3 प्रतिशत ब्याज देगा। इससे पहले एसबीआई बचत बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक की बचत जमा पर 3.25 प्रतिशत ब्याज दिया करता था। इससे नीचे की रकम पर 3 प्रतिशत ब्याज मिलता था।

एक अन्य कदम के तहत एसबीआई ने बचत खाते में औसत मासिक रकम (एएमबी) का प्रावधान भी समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही बैंक अब ग्राहकों को एसएमएस भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लेगा। पहले एसबीआई एमएबी नियमों का पालन नहीं करने पर 5 से 15 रुपये तक जुर्माना लगाता था। इस जुर्माने पर अलग से कर भी लगाता था।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

रजनीश कुमार
चेयरमैन, एसबीआई

- एसबीआई ने खाते में न्यूनतम रकम रखने की अनिवार्यता खत्म की
- एसबीआई बचत खाता धारकों को देगा 3 प्रतिशत सालाना ब्याज
- मियादी जमाओं तथा कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दरों में कटौती

सूटी में हिस्सा बेच विनिवेश लक्ष्य पूरा करेगी सरकार!

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 11 मार्च

केंद्र सरकार स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (सूटी) के तहत ऐक्सिस बैंक और आईटीसी में अपनी करीब 8,000 करोड़ रुपये मूल्य की हिस्सेदारी को 31 मार्च से पहले बेचने की तैयारी कर रही है। इस कदम से सरकार को 2019-20 में 65,000 करोड़ रुपये के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'संशोधित विनवेश अनुमान को पूरा करने में कुछ कमी रह सकती है। इसकी भरपाई के लिए दीपम सूटी में करीब 8,000 करोड़ रुपये मूल्य की हिस्सेदारी बेचेगा।' दीपम निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग है।

- 8,000 करोड़ रुपये मूल्य की हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार
- सूटी के जरिये केंद्र की ऐक्सिस बैंक और आईटीसी में है करीब 25,348 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी
- केंद्र के पास ऐक्सिस बैंक में 4.71 फीसदी और आईटीसी में 7.93 फीसदी हिस्सेदारी है
- दीपम ने पिछले वित्त वर्ष में बेचा था सूटी में 7,000 करोड़ रुपये का हिस्सा

वर्तमान में केंद्र सरकार की सूटी के जरिये ऐक्सिस बैंक में 4.31 फीसदी और आईटीसी में 7.93 फीसदी हिस्सेदारी है। बुधवार को बंद भाव के आधार पर ऐक्सिस बैंक की हिस्सेदारी का मूल्य करीब 8,211 करोड़ रुपये और आईटीसी में शेयर का कुल मूल्य करीब 17,127 करोड़ रुपये है। इसके अलावा केंद्र की सूटी के जरिये एलऐंडटी में भी 1.7 फीसदी हिस्सेदारी थी जिसे पिछले साल बेच दिया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में दीपम को 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य दिया गया था लेकिन उसने 84,972 करोड़ रुपये जुटा लिए थे। हालांकि 2020-21 के बजट दस्तावेज के अनुसार 2018-19 में वास्तविक विनिवेश प्राप्तियां 94,727 करोड़ रुपये रही थी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कोरोना से निपटने को तैयार तकनीक

समरीन अहमद और पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 11 मार्च

कोरोनावायरस ने बेंगलूरु के टेक पार्कों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिसरों, स्कूलों और कॉलेजों में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मशहूर इस शहर ने तकनीक के सहारे इससे निपटने के लिए कमर कस दी है। बेंगलूरु में अब तक कोरोनावायरस के संक्रमण के चार मामलों की पुष्टि हुई है।

संकट की इस घड़ी में अधिक से अधिक कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। स्टार्टअप कंपनियां कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल और संपर्क के लिए तरह-तरह के सॉल्यूशन ला रही हैं। उदाहरण के लिए शहर की स्टार्ट अप कंपनी ओजोनटेल ने कॉल सेंटर कंपनियों के कर्मचारियों के लिए घर से काम करना आसान बनाने के वास्ते क्लाउड आधारित एक सॉल्यूशन शुरू किया है। इससे कंपनी कॉल को डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल फोन या लैंडलाइन की तरफ मोड़ सकती है।

इसी तरह मानव संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर स्टार्ट-अप क्रेडिली कंपनियों को मुफ्त में हाजिरी प्रबंधन ऐप मुहैया करा रही है। संपर्क आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम के उलट इस वेब आधारित सत्यापन प्रणाली में मानवीय संपर्क के कारण विषाणु के प्रसार की आशंका नहीं है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी देवेंद्र खांडेगर ने कहा कि यह उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जिनमें घर से काम करने की व्यवस्था नहीं है।

बेंगलूरु की कंपनी ओला, मेडलाइफ और वनप्लस को सेवा देने वाली चेन्नई की कंपनी जोहो ने दूर से काम करने वाला टूलकिट 'रिमोटली' सबको मुफ्त में देने का फैसला किया है। इसमें 10 ऐप हैं जो व्यापक संपर्क सिस्टम बनाते हैं। स्वास्थ्य कारणों से प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी बाएजू पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त में अपनी ऐप की एक्सेस दे रही है। वे अप्रैल के अंत तक बायजू के लर्निंग प्रोग्राम डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हैं। डेल और इंटेल जैसी कई आईटी कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों से अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। लेकिन कई अभिभावकों को इसमें संतुलन कायम करना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि शहर में छोटे बच्चों के स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

- डेल और माइंडट्री के दो कर्मचारी कोरोना से संक्रमित
- देश भर में कोरोना के कुल 60 से अधिक मामले
- केरल ने इटली से लौटे 45 लोगों को निगरानी में रखा
- साई ने बंद किया बेंगलूरु केंद्र
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
- इटली में फंसे लोगों की मदद के लिए जाएगा चिकित्सा दल

(संबंधित खबर : पृष्ठ 14)

खबरों में रहे स्टॉक

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

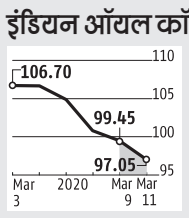

बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में ओएनजीसी को पछाड़ा

₹ 99.45 पिछला बंद भाव
₹ 97.05 आज का बंद भाव
▼ 2.41 %

कोल इंडिया

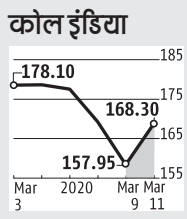

दूसरी सबसे अधिक मूल्यवान सूचीबद्ध सरकारी कंपनी बनी

₹ 157.95 पिछला बंद भाव
₹ 168.30 आज का बंद भाव
▲ 6.55 %

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस

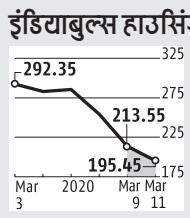

येस बैंक में अधिक निवेश की चिंता में 3 दिन में 34 फीसदी लुढ़का शेयर

₹ 213.55 पिछला बंद भाव
₹ 195.45 आज का बंद भाव
▼ 8.48 %

टाटा मोटर्स

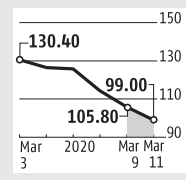

कोविड-19 झटके के बाद चीन से मांग में सुधार होने में लगेगा वक्त

₹ 105.80 पिछला बंद भाव
₹ 99.00 आज का बंद भाव
▼ 6.43 %

इंडसइंड बैंक

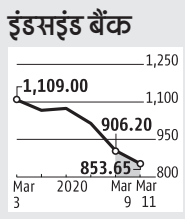

लगातार तीसरे दिन शेयर में गिरावट

₹ 906.20 पिछला बंद भाव
₹ 853.65 आज का बंद भाव
▼ 5.80 %

संक्षेप में

बैंक ऑफ इंगलैंड ने घटाई नीतिगत दरें

बैंक ऑफ इंगलैंड ने बुधवार को अपनी मुख्य नीतिगत दर को 0.5 फीसदी घटाकर 0.25 फीसदी कर दिया। कोरोनावायरस के प्रभाव से निपटने के उपाय के तहत यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस कठिन समय में इस कदम से कंपनियों को सहायता तथा ग्राहकों में भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर नए कोरोनावायरस का प्रभाव बड़ा हो सकता है। ऐसी आशंका है किआने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से कमजोर पड़ सकती हैं। बैंक ने बयान में कहा कि नीतिगत दर में कटौती कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्रों में उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिश कंपनियों और परिवारों को मदद करने के उपायों का हिस्सा है। भाषा

एनएचपीसी ने बॉन्ड के जरिये जुटाई रकम

सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी ने बुधवार को कहा कि उसने निजी नियोजन आधार पर बॉन्ड जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाया है। कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा, एनएचपीसी लि. ने 11 मार्च को सुरक्षित, विमोच्य, कर योग्य गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड के निजी नियोजन आधार पर 500 करोड़ रुपये जुटाया है। एनएचपीसी के अनुसार बॉन्ड बीएसई और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा। *भाषा*

डॉलर का शुद्ध खरीदार बना रहा आरबीआई

रिजर्व बैंक जनवरी महीने में भी डॉलर का शुद्ध खरीदार बना रहा। उसने जनवरी में हाजिर बाजार में 10.27 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली है। आलोच्य माह के दौरान रिजर्व बैंक ने 11.49 अरब डॉलर की अमेरिकी मुद्रा की खरीदारी की और 1.22 अरब डॉलर की बिक्री की। इस तरह वह 10.27 अरब डॉलर का शुद्ध खरीदार रहा। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने 4.36 अरब डॉलर की अमेरिकी मुद्रा की शुद्ध खरीदारी की थी। पिछले साल जनवरी में भी रिजर्व बैंक 29.3 करोड़ डॉलर का शुद्ध खरीदार रहा था। रिजर्व बैंक 2018-19 में डॉलर का शुद्ध बिकवाल रहा था। *भाषा*

सॉवरिन वेल्थ फंड घटा सकते हैं भारत में निवेश

तेल में गिरावट जारी रही तो बिकवाली बढ़ा देंगे विदेशी निवेशक

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 11 मार्च

अमीर तेल उत्पादक देशों द्वारा सॉवरिन वेल्थ फंडों (एसडब्ल्यूएफ) के जरिये भारत में किया जाने वाला निवेश तेल कीमतों में गिरावट की वजह से प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब, कुवैत, नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों को तेल कीमतों में आई ताजा गिरावट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये देश भारत में एसडब्ल्यूएफ के जरिये निवेश करते हैं। एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय इक्विटी में सॉवरिन वेल्थ फंडों के तहत आने वाली परिसंपत्तियों का आकार 1.82 लाख करोड़ रुपये का है।

तेल कीमतों में बड़ी गिरावट से इस ईंधन पर जोखिम की धारणा को बढ़ावा मिल सकता है जिससे एफपीआई अपना निवेश निकाल सकते हैं। एफपीआई ने पिछले 12 सत्रों में लगभग 33,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे और एसडब्ल्यूएफ की बिकवाली से हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एसडब्ल्यूएफ, मुख्य तौर पर दीर्घावधि निवेशक होते हैं।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म बोफा सिक्योरिटीज ने बुधवार को अपने वित्त वर्ष 2021 के एफपीआई निवेश प्रवाह के अनुमान में 5 अरब डॉलर तक की कमी की। ब्रोकरेज फर्म ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2021 की वृद्धि का अनुमान घटाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया है, वहीं वैश्विक मंदी की स्थिति में इसे 4.4 प्रतिशत किया गया है। विश्लेषकों के अनुसार, तेल कीमतों में गिरावट का कई प्रमुख तेल उत्पादक या निर्यातक देशों के आय स्तरों और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। खपत भी प्रभावित हो सकती है जिससे भारत समेत अन्य देशों से आयात प्रभावित होगा। तेल कीमतों में लंबे समय तक मंदी की स्थिति में कुछ देशों में सामाजिक अशांति की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

डाल्टन कैपिटल एडवाइजर्स के निदेशक यूआर भट ने कहा, 'दुनियाभर में सरकारों को विदेशी निवेशकों के बीच भरोसा लौटाने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय मोर्चे पर कदम उठाने की जरूरत होगी।'

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी का कहना है कि जहां तेल कीमतों में गिरावट से भारत की वृहद स्थिति (राजकोषीय स्थिति, मुद्रास्फीति, मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार) सुधारने में मदद मिल सकती है, वहीं यदि वैश्विक वृद्धि की रफ्तार प्रभावित होती है तो इससे निर्यात मांग पर दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'सॉवरिन वेल्थ फंडों से भारत में ताजा निवेश प्रवाह घट सकता है। हम तेल कीमतों में लंबे समय तक मंदी की स्थिति में बिकवाली देख सकते हैं।' उनका कहना है कि इस मंदी से पश्चिम एशिया के देश, रूस, नॉर्वे, कनाडा और अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है।

यूरोप और अमेरिका में कोविड-19 की महामारी से पैदा हुईं मांग वृद्धि की चिंताओं की वजह से तेल कीमतों पर दबाव पड़ा है। जेपी मॉर्गन ऐसेट मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है, '30-40 डॉलर प्रति बैरल के मौजूदा स्तर का मतलब होगा दुनियाभर में कई ऊंची लागत वाले उत्पादकों के लिए परिचालन नुकसान उठाना, जिससे आपूर्ति में कमी आएगी। हालांकि आखिरकार कीमतें अधिक टिकाऊ स्तर की ओर वापस आएंगी। फिर भी यह झटका बाजार के लिए अल्पावधि में जोखिम का कारण बना रह सकता है।'

भारत में निवेश करने वाले शीर्ष सॉवरिन फंड

फंड	देश	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर	**96,761**
गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	नॉर्वे	**24,017**
अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी	यूएई	**6,451**
सीडीपीक्यू	कनाडा	**6,411**
कामास इन्वेस्टमेंट्स	सिंगापुर	**2,430**

स्रोत : एनएसईइनफोबेस डॉट कॉम
*आंकड़ों में भारतीय शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की होल्डिंग शामिल
**31 दिसंबर, 2019 तक

तेल कीमत में गिरावट, मूल्यांकन में सहजता: लिवाली का सही समय

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 11 मार्च

वैश्विक संकेतों और घरेलू घटनाक्रम के मद्देनजर पिछले कुछ सत्रों के दौरान शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण कुल मिलाकर बाजार मूल्यांकन कहीं अधिक आकर्षक हो गया है। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि लंबी अवधि के लिहाज से शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक लिवाली के लिए इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं।

बेंचमार्क निफ्टी सूचकांक में इस साल अब तक करीब 14 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। पिछली बार, 2011 में जब यूरोपीय ऋण संकट के कारण वैश्विक निवेशक धारणा कमजोर पड़ी थी तो समीक्षाधीन अवधि में निफ्टी में कहीं अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। यह सूचकांक 17 जनवरी की अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई 12,352 अंकों से करीब 10 फीसदी लुढ़क चुका है।

जेफरीज के विश्लेषकों ने कहा कि लिवाली करने वाले निवेशकों के लिए जोखिम प्रतिफल अब कहीं अधिक अनुकूल है। इस साल की दो बड़ी वैश्विक घटनाओं का भारत पर फिलहाल कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिए उनका मानना है कि बाजार का कमजोर प्रदर्शन काफी हद तक घरेलू कारकों से संचालित है जिनमें कमजोर वृद्धि ओर बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं शामिल हैं।

जेफरीज के महेश नंदुरकर ने अभिनव सिन्हा के साथ तैयार एक रिपोर्ट में कहा है, 'निफ्टी आम सहमति वाली आय के मुकाबले 15.4 गुना वन-ईयर फॉरवार्ड प्राइस टु अर्निंग पर कारोबार कर रहा है जो दीर्घावधि औसत के अनुरूप और जनवरी 2017 के बाद सबसे कम है। बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.07 फीसदी पर वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सबसे कम है। हालांकि मूल्यांकन के उपयुक्त होने के कारण हमारा मानना है कि जोखिम प्रतिफल अब कहीं अधिक अनुकूल है।'

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने भी लगभग इसी तरह की राय जाहिर की। उनका कहना है कि शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिहाज से दमदार बुनियाद वाली कंपनियों पर विचार किया जा सकता है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनोद कार्की और सिद्धार्थ गुप्ता ने एक हालिया नोट में लिखा है, 'फिलहाल निफ्टी 50 सूचकांक का आय प्रतिफल बॉन्ड प्रतिफल के मुकाबले 45 आधार अंक अधिक है और इससे पता चलता है कि अतीत में उच्च प्रत्याशित प्रतिफल मिले हैं। इसके उदारहण में नोटबंदी (44 आधार अंक) और टेपर टेंट्रम (44 से अधिक आधार अंक) शामिल हैं। नीति निर्माताओं के एहतियाती कदम को ध्यान में रखते हुए हम वैश्विक मंदी की काफी कम आशंका जाहिर करते हैं। हमारा मानना है कि आय प्रतिफल का मौजूदा परिदृश्य बॉन्ड प्रतिफल को पार कर जाएगा जो शेयर खरीदने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।'

प्रोत्साहन की उम्मीद

विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक वित्तीय संकट, नोटबंदी और टेपर टेंट्रम जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के विपरीत कोविड-19 प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक नजर रखी जा रही है। राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन के जरिये सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मंदी की आशंका कम होगी।

मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने कहा, 'इस प्रकोप के मद्देनजर नीतिगत उपाय पहले ही किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि आगामी महीनों में कहीं अधिक सुगमता दिखेगी। वैश्विक मौद्रिक सुगमता चक्र का भी विस्तार होगा क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2020 की दूसरी तिमाही में 75 आधार अंकों की कटौती की है जबकि यूरोपीयन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान तात्कालिक तौर पर परिसंपत्ति खरीदारी बढ़ा रहे हैं। उभरते बाजारों के अधिकतर केंद्रीय बैंक भी आगे दरों में कटौती करेंगे जिससे वैश्विक मौद्रिक नीति दरे एक नई सर्वकालिक निचले स्तर पर होंगी।'

कोरोना की चिंता में टाटा मोटर्स का शेयर लुढ़का

बुधवार को टाटा मोटर्स का शेयर 4 सितंबर, 2009 के बाद से पहली बार 100 रुपये से नीचे आ गया था। जगुआर लैंडरोवर ऑटोमोटिव पर कोरोनावायरस के प्रभाव से निवेशकों में चिंता बढ़ी है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जेएलआर के सबसे बड़े बाजारों में शामिल यूरोप के कई देशों में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 98.9 रुपये के निचले स्तर को छूने के बाद कंपनी का शेयर 6.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99 रुपये पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स ने कैलेंडर वर्ष 2020 में अब तक बाजार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है और इसमें 50 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है जो समान अवधि में बीएसई के सेंसेक्स में 15 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में काफी ज्यादा है। *बीएस*

कर्ज में 70 फीसदी की कटौती करेगी एस्सार

अदिति दिवेकर
मुंबई, 11 मार्च

रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार समूह ने कर्ज घटाने की अंतिम कवायद शुरू कर दी है क्योंकि तेल व स्टील कारोबार बेचने के बाद उसकी योजना बाकी कर्ज में 70 फीसदी की कटौती कर 12,000 करोड़ रुपये पर लाने की है। वित्त वर्ष 2017 में कुल कर्ज 1.83 लाख करोड़ रुपये था, जिसे समूह पिछले तीन साल में घटाकर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर ला चुका है। अब उसकी योजना बाकी कर्ज को 42,000 करोड़ रुपये से घटाकर 12,000 करोड़ रुपये पर लाने की है। एस्सार समूह ने नीति निर्माताओं और ब्यूरोक्रैट को भेजे पत्र में यह जानकारी दी है।

बिजली कारोबार में कर्ज में 60 फीसदी की प्रस्तावित कटौती (12,000 करोड़ रुपये) और बाकी पोर्टफोलियो कारोबार में इतनी ही कर्ज कटौती के बाद एस्सार समूह मोटे तौर पर लंबी अवधि वाला सावधि कर्ज चुका देगा।बाकी 30,000 करोड़ रुपये

का कर्ज समूह की पूर्ण रूप से परिचालित परिसंपत्तियों में कार्यशील पूंजी के जरूरत के लिए है। समूह बढ़त के नए चरण की ओर बढ़ रहा है और अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को रफ्तार दे रहा है। समूह के प्रवर्तकों रवि रुइया और प्रशांत रुइया ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिसंपत्तियां बेचने के बाद भारत व विदेश में समूह की तेल व गैस, बंदरगाह, बिजली, जहाजरानी और खनन परियोजनाओं में रुचि है, जो उसे एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व देता है।

इस पत्र में यह भी कहा गया है कि राजस्व वित्त वर्ष 2019 के 94,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 98,000 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। साथ ही 2020-21 में 1,01,000 करोड़ रुपये और उसके एक साल बाद 1,04,000 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है।

एस्सार ने कहा कि उभरते देसी परिदृश्य व आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए कर्ज घटाने के सतर्क रुख के बाद कंपनी हल्की बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़ रही है।

पत्र में कहा गया है, मजबूत कंपनियों के हमारे पोर्टफोलियो लगातार अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और उनका संयुक्त राजस्व 1 लाख करोड़ ररुपये है। एस्सार ने कहा कि बंदरगाह, स्टील, तेल रिफाइनिंग और ईंधनों की खुदरा बिक्री, तेल व गैस खोज व उत्पादन, बिजली उत्पादन व पारेषण, खनन, जहाजरानी और दूरसंचार में उसने 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है।

संकटग्रस्त येस बैंक में निवेश का मामला

जेसी फ्लावर्स, टिल्डेन, सेरबरस की रुचि

पीई फर्म 10 रुपये प्रति शेयर पर हिस्सा लेना चाहती है, एसबीआई से योजना बनाने को कहा

हंसिनी कार्तिक और सुरजीत दास गुप्ता
मुंबई/नई दिल्ली, 11 मार्च

येस बैंक में साथ मिलकर निवेश के लिए भारतीय स्टेट बैंक की बातचीत दिचलस्पी रखने वाले खरीदारों से आगे बढ़ी है, लेकिन समझा जाता है कि वैश्विक प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने इस सौदे के लिए दो अहम शर्तें रखी है।

जनवरी से ही येस बैंक के साथ बातचीत कर रही जेसी फ्लावर्स और टिल्डेन पार्क कैपिटल और सेरबरस कैपिटल ने हाल में इस बैंक में दिलचस्पी दिखाई है। इन्होंने कहा है कि येस बैंक की परिसंपत्ति व देनदारी का साफ सुथरा करने की योजना एसबीआई के पास होनी चाहिए। एक सूत्र ने कहा, पीई निवेशकों ने एसबीआई से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एटी-1 बॉन्डों व टियर-2 बॉन्डों को बट्टे खाते में डाल दिया जाए।

सूत्र ने कहा, बैंक में रकम झोंकने के बाद ये निवेशक बॉन्डधारकों के पिछले बकाए को लेकर आशंकित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 6 मार्च को पेश पुनर्गठन योजना के मसौदे में एटी-1 बॉन्डों को बट्टे खाते में डाले जाने का जिक्र है, हालाकि यह मसौदा टियर-2 बॉन्ड को लेकर मौन है। सामान्य परिस्थितियों में टियर-2 बॉन्डों को पबट्टे खाते में डालने की इजाजत नहीं होती। भवन एसपीजेआईएमआर के प्रोफेसर अनंत नारायण ने कहा, हालांकि जब आरबीआई बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 की शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो यह उसे थोड़ी छूट देता है।

समझा जाता है कि पीई निवेशकों ने एसबीआई को बैंक के दबाव वाले संभावित कर्ज की पहचान और उन्हें संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को हस्तांतरित करने को कहा है। एक अन्य सूत्र ने कहा, हम जानते हैं कि एआरसी की तरफ से खरीद के बाद भी इन परिसंपत्तियों से ज्यादा रकम नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा मकसद खाता बही को साफ सुधरा करने का है।

फंडों ने येस बैंक में निवेश की इच्छा जतानी शुरू की है जबकि बट्टे खाते में डाले जाने के कारण बैंक को दिसंबर तिमाही में अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। एक सूत्र ने कहा, निवेशक चाहते हैं कि बैंक में रकम लगाने के बाद परिसंपत्ति गुणवत्ता की कोई नई समस्या नहीं उभरे।

यह भी समझा जाता है कि अगर एसबीआई इन शर्तों पर सहमत होता है तो पीई निवेशक एस्क्रो खाते में 50 करोड़ डॉलर की राशि अग्रिम जमा कराने के इच्छुक हैं और येस बैंक में 1 से 1.2 अरब डॉलर और निवेश कर सकते हैं। जेसी फ्लावर्स ने इस पर टिप्पणी नहीं की, वहीं टिल्डेन पार्क कैपिटल को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। ब्लैकस्टोन ने भी इस पर टिप्पणी नहीं की।

कीमत के लिहाज से ये निवेशक एसबीआई के सामने की कई 10 रुपये प्रति शेयर की पेशकश के समान पेशकश चाहते हैं। एक बैंकर ने कहा, चूंकि ये कंपनियां एसीबआई के साफ पूंजी देगी, लिहाजा कीमत के लिहाज से भी वह एसबीआई के समान व्यवहार चाहते हैं। कीमत पर अभी विचार हो रहा है, लेकिन बैंकरों का मानना है कि नियामकीय छूट दी जा सकती है। समझा जाता है कि एसबीआई देसी फंड हाउस से संपर्क कर येस बैंक की अल्पावधि वाली प्रतिभूतियों में और निवेश करने को कह रहा है। साथ ही एसबीआई ने सरकारी बैंकों से येस बैंक में थोक जमा झोंकने के लिए बात कर रहा है जब 3 अप्रैल को बड़ी जमाओं की निकासी से पाबंदी हट जाएगी।

येस बैंक के लिए योजना

- पीई फर्म जेसी फ्लावर्स, टिल्डेन पार्क व सेरबरस कैपिटल कर रही है हिस्सा लेने पर बात
- 10 रुपये प्रति शेयर पर करीब 1 अरब डॉलर निवेश की पेशकश
- ये कंपनियां चाहती है कि येस बैंक की परिसंपत्ति व देनदारी को ठीक करे एसबीआई
- एटी-1 बॉन्ड व टियर-2 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने की मांग
- दबाव वाली 90,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां बेचने का सुझाव
- अल्पावधि कर्ज जुटाने के लिए देसी फंडों व बैंकों से बातचीत कर रहा है स्टेट बैंक

30 हजार करोड़ रुपये के फंसे कर्ज में राणा कपूर की भूमिका की जांच

पृष्ठ-1 का शेष

इनसे जुड़े दस्तावेज हासिल किए जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल यह तय करने में किया जाएगा कि येस बैंक से रकम का हस्तांतरण इन कंपनियों को तो नहीं किया गया। निदेशलय ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर और तीन पुत्रियों रोहिनी कपूर, राधा कपूर और राखी कपूर को इस मामले में आरोपी बनाया है।

हर लेनदेन का विस्तृत विश्लेषण पेश करते हुए ईडी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस मामले में आरोपी ने हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी की। आरोपी ने इस काली कमाई के वैध होने का दावा किया। इससे पहले ईडी ने इसी अदालत में 8 मार्च को 4,300 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात कही थी और कपूर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। यह शुरुआती अनुमान है जो बयान, तलाशी के दौरान जब्ती आदि पर आधारित है। ईडी के मुताबिक, येस बैंक का कुल कर्ज 2.25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जिसमें से करीब 42,000 करोड़ रुपये कथित तौर पर एनपीए बन गए।हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए निदेशालय ने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि कपूर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इस मामले की जरूरी सूचना नहीं मुहैया कराई है। गड़बड़ी का पता लगाने के लिए लगातार पूछताछ की दरकार है और अगर हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो जांच पर असर पड़ सकता है।

ईडी ने कहा कि कपूर को उन लोगों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की जरूरत है जिसके बयान पिछले कुछ दिनों में दर्ज किए गए हैं। इसकके साथ ही धनशोधन से जुड़ी बड़ी रकम के वास्तविक इस्तेमाल के बारे में भी उनसे जानकारी हासिल करने की जरूरत होगी। ईडी ने अदालत को बताया कि कपूर मामले से जुड़े कुछ अहम तथ्यों का खुलासा कर सकते हैं जिसकी जानकारी केवल उन्हीं को है क्योंकि बैंक के कामकाज से वे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और एक अहम अधिकारी थे।कपूरा के वकील ने तर्क किया कि उन्हें पिछले प्रबंधन की गड़बड़ियों (पूर्व सीईओ रवनीत गिल के कार्यकाल में) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कपूर ने कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद येस बैंक का बाजार पूंजीकरण 93,000 करोड़ रुपये से घटकर 5,000 करोड़ रुपये रह गया।

ईडी अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी येस बैंक के संस्थापक का कुछ कारोबारी इकाइयों को कर्ज आवंटित करने तथा पत्नी के खाते में रिश्वत लेने के आरोपों के संबंध की भी जांच की जा रही है।येस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) से 3,700 करोड़ रुपये का डिबेंचर खरीदा था जबकि डीएचएफएल ने कपूर की बेटी की एक कंपनी को 600 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।दोनों ही लेनदेन संदिग्ध हैं क्योंकि कपूर की बेटी की कंपनी का कुछ खास कारोबार या संपत्तियां नहीं हैं।

देश-विदेश में कपूर की कई संपत्तियों की पहचान

जांच एजेंसी ने कपूर और उनके परिवार द्वारा देश और विदेश में खरीदी गई करीब दर्जन भर संपत्तियों को चिह्नित किया है। इन संपत्तियों को विभिन्न कंपनियों से मिले रिश्वत के पैसों से खरीदने के आरोप है। ईडी अस्थायी तौर पर इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए उनकी सूची तैयार कर रही है। शुरुआती सूची के अनुसार कपूर और उनके परिवार के पास न्यूयॉर्क (2.06 करोड़ पाउंड) और लंदन (3 करोड़ पाउंड) में दो लक्जरी होटल और लंदन में दो अपार्टमेंट (1.5-1.5 करोड़ पाउंड) हैं। इसके अलावा दिल्ली में जोरबाग सहित विभिन्न पॉश इलाकों में चार से छह बंगले और मुंबई में करीब 6 संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। *बीएस*

येस बैंक बेचेगा वोडाफोन आइडिया का कर्ज

बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नकदी बढ़ाने में करेगा बैंक

देव चटर्जी
मुंबई, 11 मार्च

येस बैंक अब वोडाफोन आइडिया को दिए 4,000 करोड़ रुपये कर्ज की बिक्री परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों या अन्य संस्थानों को करने की योजना बना रहा है ताकि इससे मिलने वाली रकम से नकदी में इजाफा किया जा सके। सूत्र न यह जानकारी दी।

वोडाफोन आइडिया को 54,000 करोड़ रुपये बकाया चुकाने के लिए कहे जाने के बाद दूरसंचार कंपनी को दिए कर्ज को विश्लेषकों ने येस बैंक के लिए बड़ा जोखिम बताया है। वोडाफोन आइडिया के अलावा बैंक के दबावग्रस्त खातों में एस्सेल समूह, एडीएजी समूह, डीएचएफएल और वाणिज्यिक रियल एस्टेट लोनबुक शामिल है। सूत्रों ने कहा, वोडाफोन आइडिया के अलावा अन्य अच्छे कॉरपोरेट लोन भी छूट के साथ बिक्री के लिए रखे गए हैं।

डीएचएफएल को दिए कर्ज जैसे कुछ कर्ज के खरीदार शायद नहीं मिलेंगे क्योंकि यह कंपनी जांच के घेरे में है, लेकिन प्रवर्तकों की बेहतरी व अच्छे भविष्य के कारण वोडाफोन आइडिया के कर्ज के खरीदार मिल सकते हैं। दूरसंचार फर्म के कर्ज को इस साल फरवरी में डाउनग्रेड कर केयर रेटिंग्स ने नकारात्मक निहितार्थ के साथ बीबी (नकारात्मक) कर दिया था। एक सूत्र ने कहा, कंपनी की तरफ से एजीआर के बकाए का एक हिस्सा सरकार को चुकाना बताता है कि उसका इरादा गंभीर है। अगर सरकार एजीआर के भुगतान पर कुछ मोहलत देती है तो यह कर्ज दबाव की श्रेणी में नहीं जाएगा। भारतीय बैंकों का कंपनी पर कुल कर्ज 1.2 लाख करोड़ रुपये है।

भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही बैंकों से मानक दूरसंचार कर्ज और एनपीए में जाने की संभावना वाले इस क्षेत्र के विशिष्ट कर्ज पर अतिरिक्त प्रावधान के लिए कह चुका है।

जेपी मॉर्गन ने कहा कि बैंक की रिकवरी की प्रक्रिया में मजबूती आ सकती है अगर बैंक दबाव वाले कर्ज की वसूली में सक्षम हो, खास तौर से एडीएजी को दिए करीब 1.8-2 अरब डॉलर के कर्ज पर। ग्लोबल बैंक ने कहा, हमारा मानना है एसेल व एडीएजी जैसे कुछ समूह के मामले में येस बैंक के पास जमानत काफी मजबूत है और इन्हें बेचने में समस्या हो सकती है क्योंकि कुछ इकाइयां दिवालिया के घेरे में है।

मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में वोडाफोन आइडिया की कुल परिचालन आय 34,076 करोड़ रुपये रही है जबकि ब्याज, पट्टा, ह्रास व कर पूर्व लाभ 11,405 करोड़ रुपये जबकि शुद्ध नुकसान 62,234 करोड़ रुपये। एजीआर बकाए के भुगतान पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रावधान किए जाने आदि से नुकसान बढ़ा है। टैरिफ में इजाफे से कंपनी के एआरपीयू का स्तर मौजूदा 109 रुपये से बढ़ सकता है।

येस बैंक का कर्ज*

बीबी रेटिंग व इससे नीचे	**31,400** करोड़ रुपये
रियल एस्टेट लोनबुक	**6,000** करोड़ रुपये
वोडाफोन आइडिया	**4,000** करोड़ रुपये
कुल दबाव वाला कर्ज (ज्ञात)	**41,000** करोड़ रुपये
दबाव वाले अज्ञात खाते	**5,000** करोड़ रुपये
कुल दबाव वाले कर्ज	**46,000** करोड़ रुपये

स्रोत : जेपी मॉर्गन

वोडा आइडिया के अलावा अन्य अच्छे कॉरपोरेट लोन भी छूट के साथ बिक्री के लिए रखे गए हैं

शुक्रवार को कैबिनेट में येस बैंक की योजना को मंजूरी!

सोमेश झा
नई दिल्ली, 11 मार्च

संकट में फंसे येस बैंक के सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी की दरकार होगी, जिस पर कैबिनेट शुक्रवार को मंजूरी दे सकता है। सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा, येस बैंक लिमिटेड पुनर्गठन योजना 2020 का मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

बैंक के बोर्ड पर नियंत्रण और उधारी व निकासी की सीमा लगाए जाने एक दिन बाद यानी पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने पुनर्गठन योजना का मसौदा सार्वजनिक कर दिया था। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक व अन्य हितधारकों से सोमवार तक टिप्पणी मांगी थी। एसबीआई, येस बैंक की 49 फीसदी हिस्सेदारी ले सकता है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार से मुलाकात की थी। योजना के मसौदे पर मिली टिप्पणी की जांच के बाद आरबीआई प्रावधानों में संशोधन कर सकता है और उसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज सकता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के मुताबिक, केंद्र सरकाकर बिना किसी संशोधन या कुछ बदलाव के साथ उसे मंजूरी दे सकती है, जैसा व उचित समझे।

यह योजना सरकार की तरफ से तय तारीख से लागू हो जाएगी और योजना के अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीख भी हो सकती है। सरकारी की मंजूरी के बाद इस योजना की प्रति संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

आरबीआई ने येस बैंक पर कई पाबंदियां लगाई है जिसमें नई उधारी और ग्राहकों की तरफ से 50,000 से ज्यादा रकम की निकासी पर रोक शामिल है। आरबीआई ने एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। कुमार ने कहा था कि मौजूदा हफ्ते के आखिर तक पाबंदी हटाई जा सकती है।

योजना की मंजूरी के बाद आरबीआई येस बैंक का नया निदेशक मंडल नियुक्त करेगा। इसमें एसबीआई के दो सदस्य होंगे। एसबीआई शुरू में इस बैंक में 2,450 करोड़ रुपये निवेश करेगा, जो 10,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है, लेकिन यह बैंक की पूंजी की जरूरत पर निर्भर होगा। ये बातें पिछले हफ्ते एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कही थी।

येस बैंक के शेयर पर भारी भरकम एसएलबी प्रीमियम

बीएसई पर येस बैंक 35.53 फीसदी चढ़ा

सचिन मामबटा
मुंबई, 11 मार्च

येस बैंक के शेयरधारक सिक्योरिटीज लेंडिंग ऐंड बॉरोइंग (एसएलबी) स्कीम के जरिए शेयर उसे उधार देने के लिए भारी प्रीमियम वसूल रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, येस बैंक में संकट के बीच नकदी बाजार और वायदा में कीमतों के अंतर ने इसमें योगदान किया है। येस बैंक के शेयर की सालाना उधारी लागत 244.6 फीसदी है। यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के आंकड़ों से मिली।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख योगेश राधके ने कहा, यह प्रीमियम मोटे तौर पर नकदी बाजार और वायदा बाजारों में कीमत के अंतर के चलते है। वायदा बाजार में नकदी बाजार की कीमत के मुकाबले 20-30 फीसदी प्रीमियम पर कारोबार हो रहा है। एसएलबी के क्षेत्र में ज्यादा प्रीमियम इस अंतर को प्रतिबिंबित करता है क्योंकि आबिट्रेज में लगे लोग नकदी बाजार में बिकवाली और वायदा बाजार में खरीदारी करते हैं। एसएलबी की वव्यवस्था के जरिये वे शेयर उधार देते हैं ताकि ट्रेड पूरा हो जाए।

उन्होंने कहा, येस बैंक के शेयरों में नकदी आधारित खरीद हो रही है, लेकिन वायदा बाजार अभी भी इसे नहीं समझ पा रहा है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव व टेक्निकल विश्लेषक चंदन तापड़िया ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने चेताया कि उच्च उतारचढ़ाव से जोखिम बढ़ सकता है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग ऐंड बॉरोइंग की व्यवस्था लंबी अवधि के निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो पर अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित करने का मौका देता है और वह अपनी प्रतिभूतियां शुल्क के बदले देते हैं।

अन्य शेयर जिनके प्रतिफल पर नजर रखी जा सकती है उनमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक और पावर ग्रिड शामिल है। इनका सालाना प्रतिफल 17 से 34 फीसदी के दायरे में है। वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद येस बैंक पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार भारतीय स्टेट बैंक के साथ अन्य निवेशकों को जोड़ रही है ताकि बैंक की पूंजी की जरूरत पूरी करने में मदद मिले। तब से इस शेयर में उतारचढ़ाव रहा है। बुधवार को बीएसई पर येस बैंक का शेयर 35.53 फीसदी चढ़ा। 52 हफ्ते का उच्चस्तर 285.9 रुपये है जबकि निचला स्तर 5.55 रुपये।

येस बैंक के क्लाइंटों को एसबीआई कार्ड आईपीओ में आवंटन

अन्य बैंक खाते से भुगतान के लिए मिला दो दिन का समय

श्रीमी चौधरी और समी मोडक
मुंबई, 11 मार्च

एसबीआई कार्ड्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में येस बैंक के खाते के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को इस शर्त पर शेयरों का आवंटन किया गया है कि वे अन्य बैंक खाते से शुक्रवार से पहले भुगतान कर देंगे। सूत्र ने यह जानकारी दी। इससे यह अनिश्चितता दूर हो गई कि क्या येस बैंक के क्लाइंटों को शेयरों का आवंटन किया जाएगा क्योंकि येस बैंक पर आरबीआई ने 30 दिन की रोक लगा दी है। 10,300 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री के लिए बुधवार को आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया।

आईपीओ के लिए येस बैंक के खातों से करीब 1,500 करोड़ रुपये की बोली लगी थी। ज्यादातर आवंटन क्यूआईबी को किए गए हैं, जिसके बाद अति धनाढ्य निवेशक का स्थान है। सूत्रों ने कहा कि येस बैंक के खातों के लिए खुदरा निवेशकों ने करीब 150 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स स्टॉक एक्सचेंजों में शुक्रवार को सूचीबद्ध होगी। अगर येस बैंक के क्लाइंट दो दिन के भीतर भुगतान में नाकाम रहते हैं तो आईपीओ का ओएफएस हिस्सा घटा दिया जाएगा। यह जानकारी बैंकर ने दी।

इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक और प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल मूल योजना से थोड़ा कम विनिवेश करेंगे। एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नए शेयर और एसबीआई व कार्लाइल की तरफ से क्रमश: 4 व 10 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश हो रहा है।

बाजार के प्रतिभागी निवेशकों की तरफ से भुगतान न किए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। एक ब्रोकरेज फर्म के अधिकारी ने कहा, कुछ निवेशकों के अन्य बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं भी हो सकती है। वहीं अन्य बाजार में उतारचढ़ाव को देखते हुए जानबूझकर भुगतान नहीं कर सकते हैं।

एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ गुरुवार को बंद हुआ। तब से बाजार में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि गिरावट के कारण एसबीआई कार्ड्स आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 फीसदी से घटकर 5 फीसदी के नीचे चला गया है।

एसबीआई कार्ड्स आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 फीसदी से घटकर 5 फीसदी के नीचे चला गया है

स्टेट बैंक ने घटाई जमा पर ब्याज दरें

पृष्ठ-1 का शेष

एसबीआई ने बुधवार को कहा कि इसके सभी 44.51 करोड़ बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समय ग्राहकों को महानगरों में बचत खाते में न्यूनतम 3,000 रुपये, कस्बाई क्षेत्रों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये रखना होता है। एसबीआई ने सीमांत लागत उधारी पर आधारित उधारी दर (एससीएलआर) में 10 से 15 आधार अंक कटौती की घोषणा की है। यह कटौती सभी अवधि के लिए लागू होगी। नई दर 10 मार्च 2020 से प्रभावी हो गई है।

इस कटौती के बाद एक वर्ष की एमसीएआर अब 7.75 प्रतिशत रह गया है, जो पहले 7.85 प्रतिशत थी। अप्रैल 2029 में एमसीएलआर 8.5 प्रतिशत थी। एसबीआई के इस कदम से आवास ऋण पर मासिक किस्त (ईएमआई) भी कम हो जाएगी। अब 30 वर्ष की अवधि के ऋण पर प्रति 1 लाख रुपये ग्राहकों को करीब 7 रुपये कम भुगतान करना होगा। 7 वर्ष के कार ऋण भी ईएमआई प्रति 1 लाख रुपये 5 प्रतिशत कम हो जाएगी। बैंक ने सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) पर ब्याज में भी 10 माच 2020 से बदलाव किया है। बैंक ने 7-45 दिनों की अवधि की जमाओं पर ब्याज 50 आधार अंक कम किया गया है, जबकि 1 वर्ष और इससे अधिक अवधि की जमाओं पर ब्याज 10 आधार अंक घटाया गया है। बैंक अब 7-45 दिनों की जमाओं पर ब्याज 5 प्रतिशत ब्याज देगा, जो पहले 4.5 प्रतिशत हुआ करता था।

येस बैंक के शीर्ष प्रबंधन से ईसॉप्स, बोनस वापस लेने पर विचार

पृष्ठ-1 का शेष

येस बैंक का मामला आरबीआई के लिए पहला स्पष्ट और संभवत: सबसे खराब कसौटी है क्योंकि एफएसबी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर नजर रखता है और इसका गठन अप्रैल 2009 में जी20 के लंदन शिखर सम्मेलन के बाद किया गया था। इसने फाइनैंशियल स्टैबिलिटी फोरम का स्थान लिया था। येस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को दिए गए ईसॉप्स और बोनस को वापस लेने के फैसले को अगर लागू किया जाता है तो इसका प्रभाव बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35ए को लागू करने के बराबर होगा।

यह केंद्रीय बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक या कर्मचारी को तलब करने का अधिकार देता है। केंद्रीय बैंक के 85 साल के इतिहास में कभी भी इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

दूसरे निजी बैंकों और उनके शीर्ष प्रबंधन के प्रदर्शन की भी गहन जांच हो सकती है और वित्त वर्ष 2019 तथा वित्त वर्ष 2020 के लिए ईसॉप्स और बोनस के भुगतान में देरी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2018 में निजी बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों को स्टॉक ऑप्शन और बोनस के भुगतान को मंजूरी देने में समय लगाया था और यह भुगतान वित्त वर्ष 2019 के पूरा होने के बाद ही किया गया था। बैंकिंग नियामक ने सभी निजी बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके वित्त वर्ष 2020 के बहीखातों की गहराई से जांच होगी। साथ ही वह संभावित व्हिसल ब्लोअर को भी जागने का संकेत दे रहा है। येस बैंक के मामले में उसके बहीखाते को हुए नुकसान का पता 14 मार्च को ही लग पाएगा। भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है और जाहिर है कि वह इस निजी बैंक के खातों की पूरी जांच पड़ताल करेगा।

मुंबई में ईडी कार्यालय के बाहर राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर

येस बैंक को अब ज्यादा ऑनलाइन भुगतान मुमकिन

येस बैंक के ग्राहक अब अपने क्रेडिट कार्ड तथा 2 लाख रुपये से अधिक कर्ज की किस्तों का भुगतान भी दूसरे बैंक से ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। एस बैंक ने बुधवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। बैंक ने एक ही दिन पहले क्रेडिट कार्ड या कर्ज के बकाए के भुगतान के लिए अन्य बैंक के खातों से आईएमपीएस तथा एनईएफटी की सुविधा पुन: शुरू की थी। अब बैंक ने इस तरह के भुगतान के लिए आरटीजीएस सेवाएं भी शुरू कर दी है। आरटीजीएस के जरिए 2 लाख रुपये से अधिक के भुगतान किए जा सकते हैं। एनईएफटी के जरिए 2 लाख रुपये तक के भुगतान की ही सुविधा है। बैंक ने एक ट्वीट में कहा कि बकाया रकम के भुगतान के लिए आरटीजीएस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुप्रबंधन के मद्देनजर एस बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है।

बकाया सुरक्षित : अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने बुधवार को कहा कि येस बैंक से उसने जो भी कर्ज लिया है, वह पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी ने कहा कि ये ऋण कारोबार के लिए सामान्य तरीके से प्राप्त किए गए हैं। कंपनी ने कहा कि वह अपनी संपत्तियां बेच कर बैंक के सारे बकाए कर्ज का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि राणा कपूर, उनकी पत्नी या पुत्रियों अथवा कपूर परिवार द्वारा नियंत्रित किसी भी इकाई में हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर निवेश नहीं है। *भाषा*

मोबाइल, टेक्सटाइल व उर्वरक पर बढ़ेंगी जीएसटी की दरें!

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 11 मार्च

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूते, टेक्सटाइल तथा उर्वरकों पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में इजाफा किया जा सकता है, जिससे उल्टे शुल्क ढांचे को सही किया जा सके तथा राजस्व संग्रह में इजाफा हो।

साथ ही, प्रत्येक महीने एक करोड़ रुपये की इनाम राशि वाली मासिक लॉटरी योजना को भी जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा जिससे इसके ग्राहकों को इनवॉइस संग्रह के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'जीएसटी के तहत उल्टे शुल्क ढांचे की व्यवस्था को सही किया जाने की आवश्यकता है। मोबाइल फोन, फैब्रिक और दूसरी वस्तुओं की दरों में सुधार देखा जा सकता है।' जब कच्चे माल पर अंतिम उत्पाद से अधिक जीएसटी दरें लगाई जाती हैं तो इसे उल्टे शुल्क ढांचे की व्यवस्था कहा जाता है। इसके चलते उच्च इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) देखा जा सकता है। एक पंजीकृत करदाता कच्चे माल पर अधिक कर तथा अंतिम उत्पाद पर कम शुल्क की स्थिति में गैर-दावा आईटीसी के रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है।

उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत हैं जबकि फोन के हिस्सों तथा बैटरियों पर यह 18 प्रतिशत है। परिणामस्वरुप यह उल्टे शुल्क ढांचे की व्यवस्था में आता है। ऐसे मामले में मोबाइल फोन के लिए भी दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मोबाइल फोन के मामले में पिछले वर्ष एक अकेले फोन निर्माता ने करीब 4,100 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था। फैब्रिक पर भी जीएसटी दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिससे उल्टे कर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। विभिन्न श्रेणियों के कच्चे धागों (यार्न) पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता है। शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने फैब्रिक निर्माताओं को आईटीसी रिफंड का दावा करने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन बाद में जुलाई 2018 की बैठक के बाद यह अनुमति दे दी गई।

ग्राहकों को इनवाइस मांगने को प्रोत्साहित करने के लिए लॉटरी योजना होगी, जिसमें 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक हर महीने पुरस्कार दिया जा सकता है।

ग्राहक कल्याण कोष, जहां मुनाफाखोरी रोधी प्रक्रिया का धन जमा दिया जाता है, का इस्तेमाल भाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कार देने में किया जाएगा। विजेताओं का चयन नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा सीडब्ल्यूएफ बनाया गया है, जिसमें कंपनियों को मुनाफे की रकम उस स्थिति में जमा करना होता है, जिसमें ग्राहकों को कर घटाने का लाभ नहीं दिया जा सका है। सीडब्ल्यूएफ से मिले धन का इस्तेमाल देश के ग्राहकों के कल्याण में किया जाता है।

जीएसटी के तहत मुनफाखोरी रोधी नियम के मुताबिक अगर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कोई कटौती की जाती है तो वस्तु एवं सेवा के आपूर्तिकर्ताओं को उसका फायदा ग्राहकों को देना होता है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी दाम घटाकर ग्राहकों को देना होता है। हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिककरण ने नेस्ले को सीडब्ल्यूएफ में 90 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था, क्योंकि उसने दरों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचाया था। अधिकारी ने कहा कि लॉटरी योजना दिल्ली सरकार द्वारा मूल्यवर्धित कर के दौर में ग्राहकों के लिए शुरू की गई योजना की ही तरह है। दिल्ली सरकार ने 2015 में बिल बनाओ, इनाम पाओ योजना वैट के दौर में शुरू की थी।

महंगे होंगे सामान

- एक करोड़ रुपये इनाम राशि की लॉटरी के भी जीएसटी में आने की संभावना
- उलट शुल्क ढांचे की व्यवस्था को सही करने तथा राजस्व संग्रह में इजाफे की उम्मीद
- मोबाइल पर जीएसटी दरें 12 से बढ़कर हो सकती हैं 18 प्रतिशत
- फैब्रिक पर भी जीएसटी दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

सूटी में हिस्सा बेच विनिवेश लक्ष्य पूरा करेगी सरकार

पृष्ठ-1 का शेष

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि विनिवेश लक्ष्य में वृद्धि मुख्य रूप से सूटी में 7,000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचने से आई थी। खबरों के अनुसार सूटी के बिना सरकार 2019-20 का संशोधित लक्ष्य हासिल करने में पीछे रह सकती है।ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेल, एनएमडीसी, पीएफसी, कोल इंडिया, इरकॉन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और अन्य कंपनियों के मार्च में प्रस्तावित ओएफएस को बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए टाल दिया गया है।सूत्रों के अनुसार 31 मार्च तक एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी और नीपको की खरीद, आईआरएफसी का आईपीओ और कुछ पीएसयू की पुनर्खरीद हो सकते हैं।

वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि एनटीपीसी के इस सौदे से करीब 15,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, वहीं आईआरएफसी के आईपीओ और कुछ पीएसयू की पुनर्खरीद से 5 हजार से 7 हजार करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। दीपम ने अब तक करीब 35,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है और संशोधित विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 2019-20 के लिए कर राजस्व और कुल अनुमानित व्यय को भी संशोधित करने की बात कही थी। इसी तरह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 फीसदी से बढ़कर 3.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। दीपम ने अंतिम बार राइट्स के ओएफएस से 400 करोड़ रुपये जुटाए थे जबकि सरकार इससे करीब 1,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद कर रही थी। सरकार की बड़ी विनिवेश योजना जिनमें एयर इंडिया का निजीकरण, भारत पेट्रोलियम, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन का विनिवेश और भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ अगले वित्त वर्ष के लिए टाल दिया गया है।

मुंद्रा बंद करने का फैसला टला

अमृता पिल्लई
मुंबई, 11 मार्च

निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने अपना मुंद्रा पावर प्लांट बंद करने का फैसला 9 दिन के लिए टाल दिया है। इस संयंत्र से बिजली खरीदने वाले पांच राज्यों को भेजे गए पहले के नोटिस में कंपनी ने गुजरात स्थित इस बिजली संयंत्र को बुधवार को बंद करने की सूचना दी थी। अब कंपनी 20 मार्च तक सामान्य परिचालन जारी रखेगी।

मुंद्रा स्थित 4,000 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र से से पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को बिजली की आपूर्ति होती है। इन राज्यों को टाटा पावर ने संयंत्र बंद करने का नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की सिफारिशों को मानने और उच्च दरों पर पूरक बिजली खरीद समझौता करने में देरी कर रहे हैं। बिजली सचिव द्वारा सोमवार को बैठक के बाद कंपनी ने बंदी का फैसला टाल दिया है। टाटा पावर ने बयान में कहा, 'इस बैठक में सभी 5 राज्यों के बिजली सचिव और अधिकारी शामिल हुए और स्वीकार्य समाधान पर चर्चा की गई।' बिजली सचिव अगले 10 दिन में एक और बैठक करेंगे और इस पर 20 मार्च को या इससे पहले फैसला किया जा सकता है। टाटा पावर ने एक बयान में कहा है, 'उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनी और ठेके संबंधी मसलों और बिजली खरीद समझौते (पीपीपी) पर चर्चा हुई, जिस पर विचार के लिए सभी पक्ष सहमत हुए हैं।'

कंपनी ने कहा, 'कोस्टल गुजरात पावर (सीजीपीएल) अब 20 मार्च के फैसले तक इंतजार करेगी और तब तक मुंद्रा संयंत्र पर सामान्य परिचालन जारी रहेगा। सोमवार को सकारात्मक चर्चा और सभी पक्षों की राय जाने के बाद स्वीकार्य हल निकलने की संभावना है।'

अक्टूबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) को निर्देश दिया था कि विभिन्न राज्यों के साथ हुए बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर फिर से विचार किया जाए, जो टाटा पावर, एस्सार पावर और अदाणी पावर के साथ हुए हैं।

टाटा पावर के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक प्रवीर सिन्हा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई समाधान योजान से मुंद्रा का घाटा कम करने में मदद मिलेगी। बिजली खरीदने वाले राज्यों से उम्मीद है कि वे कैबिनेट की मंजूरी ले लेंगे और नए शुल्क के साथ सीईआरसी से संपर्क करेंगे, जो अभी लंबित है। बुधवार को जारी एक बयान में टाटा पावर ने कहा, 'नोटिस (बिजली आपूर्ति रोकने का) अभी वैध बना रहेगा और सीजीपीएल इन बैठकों के परिणाम के आधार पर बंदी करने के नोटिस को लेकर उचित फैसले पर विचार करेगी।' बयान में आगे कहा गया है कि यह विश्वास है कि मुंद्रा संयंत्र का कुछ समाधान अगले कुछ सप्ताह में निकलेगा और संयंत्र की बंदी को टाला जा सकेगा। वित्त वर्ष 2019 में मुंद्रा का सालाना नुकसान 1,700 करोड़ रुपये था। कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान मुंद्रा का नुकसान घटकरक 900 करोड़ ररुपये रह जाएगा, क्योंकि ईंधन का बेहतर प्रबंधन हुआ है।

घट रहा है नुकसान

मुंद्रा का सलाना नुकसान

2017-18	**1,783** करोड़ रुपये
2018-19	**1,654** करोड़ रुपये
2019-20	**900** करोड़ रुपये

स्रोत : टाटा पावर की सालाना रिपोर्ट
वित्त वर्ष 20 का घाटा कंपनी का अनुमान है।

प्रतिबंध हटने पर बंधन बैंक ने खोली 125 शाखाएं

बंधन बैंक ने बुधवार को कहा कि शाखाएं खोलने को लेकर उस पर लगा प्रतिबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हटाए जाने के बाद बैंक ने 15 राज्यों में 125 आउटलेट खोले हैं। इसके साथ बैंक की शाखाओं का नेटवर्क बढ़कर 1,013 हो गया है। बैंकिंग आउटलेट में डोर स्टेप बैंकिंग यूनिट और होम लोन सर्विस सेंटर भी शामिल हैं। नए आउटलेट के साथ बंधन बैंक के कुल 4,414 आउटलेट हो गए हैं। बैंक की मौजूदगी 36 में से 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हो गई है। *बीएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 21

कमी फिर उजागर

ज्योतिरादित्य सिंधिया (49) के ताजा कदम के बाद कांग्रेस नेतृत्व को जाग जाना चाहिए। उनके कांग्रेस छोड़ने को लेकर किसी को चकित नहीं होना चाहिए। सिंधिया कांग्रेस कार्य समिति के निर्णयों के प्रति खुलकर अपनी असहमति जाहिर कर रहे थे। पिछले कुछ समय से उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की कई नीतियों की सराहना करनी भी शुरू कर दी थी। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की भारी पराजय के बाद अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे का लाभ उठाने के बजाय कांग्रेस के बूढ़े होते नेतृत्व ने 73 वर्षीय सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया। ऐसा लगता है कि युवा नेताओं के पार्टी से बाहर जाने को लेकर शीर्ष नेताओं में कोई चिंता ही नहीं है। पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार (57) गत वर्ष अगस्त में सोनिया गांधी की नियुक्ति के बाद पार्टी छोड़ने वाले पहले बड़े नेता थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद सिंधिया के रिश्तेदार प्रद्योत देव बर्मन (41) ने पार्टी की त्रिपुरा इकाई की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी आला कमान से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सितंबर में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा इकाई के अध्यक्ष अशोक तंवर (44) ने विधानसभा चुनाव से पहले गहन आंतरिक मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दी।

सिंधिया की राजनीतिक वंशावली के कारण उन्हें पार्टी में बतौर राजनीतिज्ञ उनके कद से ज्यादा तवज्जो मिली। उन्होंने नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को कम अंतर से मिली जीत के बाद ही नाखुशी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। वह गुना लोकसभा सीट अपने एक पूर्व सहयोगी से हार गए थे जो भाजपा में चला गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजिय सिंह और मुख्यमंत्री कमल नाथ ने उन्हें हाशिये पर धकेल रखा था। नाथ उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और राज्य सभा की दो सीटें दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी (48) के लिए आरक्षित किए जाने की खबर थी। जानकारी यही है कि भाजपा ने सिंधिया को राज्य सभा की सदस्यता के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा किया है। सिंधिया के समर्थन में इतने विधायक हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर भी सकती है।

पार्टी के युवा नेताओं की यह असहमति कांग्रेस नेतृत्व के वैचारिक दिवालियेपन को भी दर्शाती है। पार्टी मोदी के बहुसंख्यकवादी लोकलुभावनवाद का मजबूत और विश्वसनीय जवाब नहीं दे सकी है। अनुच्छेद 370 पर उसकी प्रतिक्रिया गलत रही और नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) जैसे विवादित विषय पर भी। देव वर्मन, जितिन प्रसाद (46), सिंधिया और दीपेंद्र हुड्डा (42) समेत कई युवा नेताओं ने एनआरसी या अनुच्छेद 370 समाप्त करने का समर्थन किया। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा (43) ने टैक्सस में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। इससे पता चलता है कि मोदी युवा राजनेताओं में किस कदर लोकप्रिय हैं।

कांग्रेस कार्य समिति ने इन युवा नेताओं में से किसी से बात करने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी के पास पिछले कुछ महीनों में इतना वक्त नहीं था कि वह सिंधिया से एक बार मुलाकात कर लेते। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं पार्टी इन नेताओं की राह इसलिए तो नहीं रोक रही कि वे कहीं राहुल गांधी के लिए चुनौती न बन जाएं। गौरतलब है कि बतौर राजनेता राहुल गांधी ने भी खुद को अच्छी तरह साबित नहीं किया है। वह और उनकी बहिन अब कांग्रेस कार्य समिति के सबसे युवा सदस्य हैं। कार्य समिति की औसत उम्र 70 वर्ष है। कुलमिलाकर पार्टी खुद को खत्म करने की राह पर है। वह भी ऐसे समय में जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है।

अजय मोहंती

कोरोनावायरस के आर्थिक सबक

विश्व में कोरोनोवायरस से उत्पन्न महामारी से निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किया जाना चाहिए। विस्तार से बता रहे हैं **रथिन रॉय**

चीन से उपजी कोरोनावायरस की महामारी न तो अप्रत्याशित है और न ही दु:साध्य। परंतु यह बीमारी वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली है और इसमें अर्थशास्त्रियों के लिए भी अहम सबक छिपे हुए हैं।

वैश्वीकरण ऐसे संरचनात्मक जोखिम उत्पन्न करता है जिनको विश्लेषणात्मक ढंग से पहचानना और उसे हल करना होगा: वैश्वीकरण तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के विजयघोष का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तकनीक और नवाचार ने वे गतिरोध कम किए हैं जो उत्पादन को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी जगहों पर स्थानांतरित करने की राह मे बाधा बनते थे। इससे उत्पादन की लागत कम हुई और वैश्विक मांग में इजाफा हुआ। चीन अपने व्यापक आकार और काम के पैमाने के कारण इस ढांचागत बदलाव का सबसे बड़ा वाहक बना। चीन में कोरोनावायरस के प्रसार ने यह दिखा दिया है कि इससे ऐसे गंभीर ढांचागत जोखिम जुड़े हुए हैं जो तुलनात्मक लाभ केसिद्धांत को उलटपुलट कर सकते हैं।

वृहद आर्थिक हस्तक्षेप इस जोखिम से निपटने में काम नहीं आएंगे: फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 आधार अंक की कटौती करके तत्काल कदम उठाया। परंतु इससे अमेरिकी शेयर बाजार महज 15 मिनट के लिए ही शांत रहे। क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ऐसी कटौती पूंजी की अनिवार्य तौर पर सस्ता करती है और मुद्रास्फीति को लेकर सहनशीलता बढ़ाती है। परंतु इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के भंग होने की ढांचागत समस्या हल नहीं होती।

इस श्रृंखला के भंग होने का अर्थ यह है कि बढ़ा हुआ उपभोक्ता व्यय आपूर्ति से मेल नहीं खाएगा। इससे मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए घरेलू निवेश में वक्त लगेगा और यह केवल सस्ती पूंजी लागत पर प्रतिक्रिया देगा, बशर्ते कि कारोबारियों को यह यकीन हो कि दरों में कटौती स्थायी है और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला के चीन की आपूर्ति श्रृंखला से महंगा होने के कारण समेकित मांग में कमी नहीं आती। भारत के एक ट्रांसफॉर्मर निर्माता से हुई मेरी बातचीत से भी इस बात की पुष्टि हुई। उनकी मुनाफे में चल रही कंपनी अभी चीन से जिस कच्चे माल का आयात करती है, वह उसका उत्पादन दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। यदि उसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है तो सस्ती पूंजी की मदद से ऐसा करने के बावजूद कंपनी को अपना उत्पाद अपेक्षाकृत महंगी कीमत पर बेचना होगा। मौजूदा मांग स्तर पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में समझदारी यही होगी कि प्रतीक्षा की जाए और इस बीच उत्पादन कम किया जाए।

आपूर्ति श्रृंखला को विकेंद्रीकृत करना: आर्थिक गतिविधियां पारंपरिक तौर पर एकीकृत उत्पादन क्लस्टर में काम करती हैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक रहती है। प्रतिस्पर्धा कच्चे माल के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मुहैया कराती है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण का रुख रखती है और वे तमाम विविधतापूर्ण आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करती हैं। वैश्वीकरण और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण का अर्थ यह है केवल सबसे किफायती स्थान ही बचेगा। उस जगह पर भी प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन जगह अपने आप में एक प्रभावी एकाधिकार तैयार करती है। यदि ऐसे स्थानिक एकाधिकार को जोखिम उत्पन्न हो तो विकेंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। कोरोनावायरस महामारी निवेश संबंधी निर्णयों को जिस तरह प्रभावित कर रहा है उससे यह स्पष्ट हो गया है।

सतर्कतापूर्ण इन्वेंटरी प्रबंधन: सस्ते लॉजिस्टिक्स के दौर के पहले इन्वेंटरी प्रबंधन में पूरा ध्यान यह सुनिश्चित करने में लगाया जाता था कि किसी फर्म को आपूर्ति श्रृंखला की विसंगतियों की वजह से बाजार हिस्सेदारी में नुकसान का सामना न करना पड़े। परंतु लॉजिस्टिक्स संबंधी नवाचार और सूचना तकनीक की क्रांति ने इन्वेंटरी को कम करने को आकर्षक बना दिया है। यह रुझान पलट सकता है क्योंकि कंपनियों को यह लगने लगा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों का जोखिम बढ़ रहा है। यदि आपूर्ति श्रृंखला की बाधा के चलते जैगुआर लैंड रोवर को सूटकेस में भरकर कार के कलपुर्जे लाने पड़ें तो इन्वेंटरी पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है।

बहुपक्षीयता के खात्मे की स्थिति को पलटना होगा: यह विडंबना ही है कि वैश्वीकरण के साथ ही उसके सबसे बड़े सुरक्षा ढांचे का पतन हुआ। यह था बहुपक्षीय समन्वित कदम। यद्यपि एचआईवी एड्स संकट से निपटने में ऐसे बहुपक्षीय समन्वित कदमों को बहुत सफलता मिली थी और तेल कीमतों के कार्टलीकरण तथा ओजोन छिद्र जैसी चुनौतियों से निपटने में भी इसे मदद मिली थी लेकिन बीते तीन दशक के दौरान वास्तविक वैश्विक चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता कम होती गई। वह व्यापार और वित्तीय नियमन पर केंद्रित हो गया। कोरोनावायरस की बीमारी इस बात को भी रेखांकित करती है कि हमें बहुपक्षीय तालमेल के बारे में अधिक सक्रिय होकर सोचना होगा। खासतौर पर तब जबकियह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबद्ध हो लेकिन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और जलवायु अनिश्चितताओं तक सीमित न हो।

घरेलू मांग का महत्त्व और अल्पव्ययी लॉजिस्टिक्स: यह विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा सबक है। औषधि आपूर्ति श्रृंखला में भारत जेनेरिक दवाएं बनाता है और उन्हें यूरोप को निर्यात करता है। वह कच्चा माल चीन से आयात करता है। यूरोप की जेनेरिक दवाओं में 26 फीसदी भारत की होती हैं जबकि अमेरिका में उसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। कोरोनावायरस हमले के बाद भारत की दवा उत्पादन क्षमता के लिए गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसके चलते जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे विकसित विश्व में औषधि आपूर्ति का संकट उत्पन्न हुआ।

हमें वृद्धि में इजाफा करने के क्रम में लॉजिस्टिक्स की भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होने की कीमत और लाभ पर। इसका अर्थ अंतर्मुखी होना नहीं है बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम लॉजिस्टिक्स में मितव्ययी हैं। ऐसी लॉजिस्टिक्स श्रृंखला विकेंद्रीकृत आपूर्ति को बढ़ावा देती है और विसंगति के जोखिम को कम करती है।

भारत जैसे बड़े उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को दो बातों पर विचार करना होगा। पहला, ऐसी वृद्धि नीति अपनानी होगी जो व्यापक मांग पर आधारित हो। यह नीति लॉजिस्टिक्स आधारित निर्यात संबंधी वृद्धि से मजबूत होती है। दूसरा, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे कम लॉजिस्टिक्स के साथ बेहतर उत्पादन किया जाए। ऐसा मौजूदा विसंगतियों के दौर में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ समायोजन के लिए जरूरी है। वस्तुओं, कच्चे माल और लोगों की कम गतिविधियों के साथ स्थानीय निर्माण ज्यादा मजबूत वृद्धि की राह दिखाता है।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी के निदेशक हैं। लेख में विचार निजी हैं)

बड़े बैंकों का भविष्य करदाताओं के सहारे

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

अब बड़े बैंक धराशायी नहीं होते हैं। इन्हें या तो भारी भरकम नकदी देकर उबार लिया जाता है या किसी मजबूत बैंक के साथ इनका विलय कर दिया जाता है

निजी क्षेत्र के येस बैंक के पतन के बाद एक प्रश्न कई लोगों को सोचने पर विवश कर रहा है। वह प्रश्न यह है कि अगर वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता केवल एक बैंक के धराशायी होने के कारण अस्त-व्यस्त हो जाती है तो करदाताओं को अंशधारकों को बचाने के लिए क्यों आगे आना चाहिए?

यह प्रश्न बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अब लगभग सभी देशों में यह चलन आम हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह स्पष्टतया अनुचित है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि नैतिकता के पैमाने पर खरा नहीं उतरने के बावजूद इस तरीके को बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं है। इस पूरी स्थिति को बीमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है जब बीमा धारकों की बीमा लेने की चाह इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में भुगतान किसी दूसरे पक्ष को करना है। इस तरह, किसी योजना को लेकर परंपरागत तौर पर दी जाने वाली चेतावनी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद हम किसी बैंक को बचाने के लिए सारा दबाव करदाताओं पर डाल देते हैं।

किसी भारी भरकम बैंक को बचाने के चक्कर में करदाताओं पर दबाव डालने का चलन अब पूरी दुनिया में खुले दिल से स्वीकार किया जा रहा है। इस पूरे संदर्भ का तार 1907 के वित्तीय संकट से जुड़ा है। उस समय जे पी मॉर्गन ने कहा था कि बैंक विशेष कारोबारी संस्थान होते हैं, इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार की जरूरत होती है। उन्होंने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फेडरल रिजर्व का उद्देश्य अमेरिकी बैंक के अंशधारकों को बचाना था, लेकिन इससे भी बढ़कर इसका लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना था। यह पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है।

वित्तीय संकट की जमीन 1905 से ही तैयार हो रही थी। 1907 में यह सामान्य घटना थी और निकरबॉकर ट्रस्ट कंपनी इस धारणा की चपेट में आ गई। उसी समय कई अन्य इकाइयों का भी पतन हो गया और इन घटनाओं ने एक बड़े संकट का रूप ले लिया। हालांकि उस समय एक अंतिम अस्त्र या यूं कहें कि संकट मोचक के रूप में कोई शीर्ष इकाई मौजूद नहीं थी। इतना ही नहीं, ये कंपनियां आंतरिक तौर पर ऋण और कोलैटरल बॉन्ड के जरिये एक दूसरे से विचित्र रूप से जुड़ी हुई थीं।

लिहाजा, कई 'धनकुबेर' जे पी मॉर्गन के पास गए और वे सभी समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। आखिरकार, उन्होंने निर्णय लिया कि जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाए हैं, उन्हें रकम दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वे साथ नहीं आए तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा और एक-एक कर सभी बरबाद हो जाएंगे। अमेरिका के तत्कालीन वित्त मंत्री इस उद्देश्य के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी।

हालांकि इस बात पर सहमति जरूर बनी कि बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) के समतुल्य संस्था स्थापित करने की जरूरत है। एक ताकतवर संकट मोचन बैंक स्थापित करने की मांग बढ़ती गई और अमेरिकी संसद कांग्रेस ने अपने इस प्रस्ताव के समर्थकों की सलाह पर राष्ट्रीय मौद्रिक आयोग (नैशनल मॉनिटरी कमीशन) की स्थापना की।

इन धनकुबेरों ने नवंबर 1910 में अपनी एक बैठक बुलाई। इसमें कई लोगों ने भविष्य में वित्तीय संकट से बचने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने फेडरल रिजर्व की स्थापना की सिफारिश की और अंतत: अमेरिका के केंद्रीय बैंक की स्थापना का रास्ता साफ हो गया और यह 1913 में अस्तित्व में आ गया। यह बिल्कुल बैंक ऑफ इंगलैंड की तर्ज पर स्थापित हुआ था। 12 क्षेत्रीय बैंक और फेडरल रिजर्व ने नियम-शर्तें तय कीं, जिन पर 1915 से अमल शुरू हो गया। फेडरल रिजर्व को मुद्रा प्रबंधन का उत्तरदायित्व मिला और यह अकेले तय किया करता था कि कितनी मुद्रा छापने की जरूरत है। इसका मुख्य कार्य सरकारी बॉन्ड की खरीद-बिक्री से ब्याज दर नियंत्रित करना था। बाद में यह संकट मोचक भी बन गया और वित्तीय प्रणाली की परिस्थितियां देखते हुए आवश्यकता अनुसार मुद्राएं छापता रहा।

1930 से विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों स्विटजरलैंड के शहर बेसल में एक अलग संस्था या दूसरे शब्दों में कहें तो एक निजी क्लब के माध्यम से एक दूसरे जुड़े हैं। इस क्लब को बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के नाम से जाना जाता है। बीआईएस की वेबसाइट में कहा गया है,'बीआईएस का मकसद दुनिया के केंद्रीय बैंकों को उनकी मौद्रिक नीति एवं वित्तीय स्थायित्व में मदद करना है और इन खंडों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के तौर पर कार्य करना है।' बीआईएस कहता है कि किसी अप्रत्याशित नुकसान से निपटने के लिए किसी बैंक के पास पर्याप्त रकम होनी चाहिए।

अब हालात ये हैं कि बड़े बैंक धराशायी नहीं होते हैं। इन्हें या तो भारी भरकम नकदी देकर उबार लिया जाता है या किसी मजबूत बैंक के साथ इनका विलय कर दिया जाता है। इससे पहले 1974 में एक बड़ा बैंक हैनओवर बैंक धराशायी हुआ था और भारत की बात करें तो 1961 में पलाई बैंक का कारोबार ठप पड़ गया था। तब से करदाताओं की रकम का इस्तेमाल बैंकों को उबारने के लिए किया जा रहा है।

कानाफूसी

उत्तर प्रदेश पर जोर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दो वर्ष दूर हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में संकट के दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में युवा नेताओं और पुराने दिग्गजों के बीच तालमेल कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष पार्टी ने 10 पुराने नेताओं को निकाल बाहर किया था जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष सिंह और पूर्व विधायक सिराज मेहदी शामिल थे। इन पर अनुशासहीनता के साथ-साथ यह आरोप था कि वे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा गठित नई टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

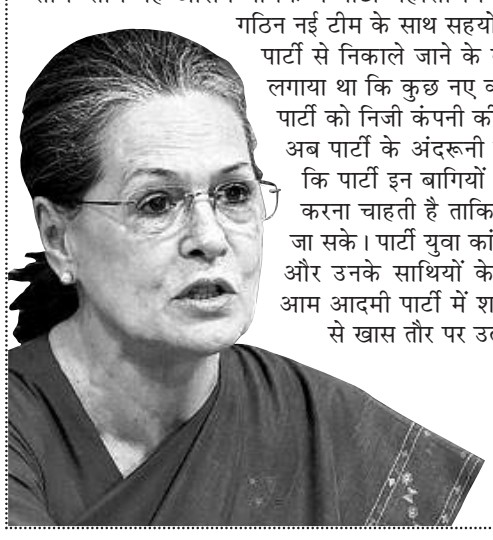

पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ नए कांग्रेसी नेता कांग्रेस पार्टी को निजी कंपनी की तरह चला रहे हैं। अब पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इन बागियों को दोबारा शामिल करना चाहती है ताकि संकट खत्म किया जा सके। पार्टी युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके साथियों के सामूहिक रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद से खास तौर पर उलझन में है।

आपका पक्ष

जनता की कमाई पर लालच की नजर

बैंकिंग व्यवस्था में विश्वसनीयता को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार नकारात्मक खबरें सुनने को मिल रही है। कुछ महीने पहले पंजाब ऐंड सिंध बैंक (पीएमसी) में घपलेबाजी की खबर हो या फिर अब येस बैंक का संकट। सभी में एक बात समान रूप से नजर आ रही है कि व्यवस्था के भीतर और बाहर बैठ लोग आपसी सांठगांठ से बड़ी चतुराई से जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ठीक है कि सरकार ने बैंक में बचत की गारंटी को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इन घोटालों का नजरअंदाज कर दिया जाए। फिर जमाकर्ताओं के विश्वास का भी प्रश्न है। बैंकों में एक ओर जहां जैसे तैसे रकम जुटा कर भविष्य के लिए पैसे जोड़ने वाले लोग हैं तो वहीं सैकड़ों करोड़ रुपये जमा करने वाला जगन्नाथपुरी ट्रस्ट भी है। इस तरह की घटनाओं का एक स्पष्ट सबक यह भी है कि कहीं न कहीं नियामक के स्तर पर घोर

बैंकिंग व्यवस्था में जमाकर्ताओं की विश्वास बहाली के लिए कदम उठाए आरबीआई

लापरवाही बरती जा रही है या फिर इसके नियमों में ही कुछ ऐसे लचर प्रावधान हैं जो बैंकर को अपने परिजनों से मिलीभगत कर पैसे हड़पने से रोक पाने में नाकाम है। इसी तरह चंदा कोछड़ पर भी आरोप है कि कैसे उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अपने पति की कंपनी को फायदा पहुंचाया था। लोकतंत्र में व्यवस्थाओं पर जनता का भरोसा ही उसके टिकाऊपन की धुरी होती है। ऐसे में सरकार और न्यायपालिका को इसका स्मरण रखते हुए व्यवस्था की ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि फिर कोई इस तरह के दुस्साहस करने से पहले बार बार सोचे। साथ ही आरबीआई को भी नियामकीय स्तर पर आमूलचूल बदलाव कर ऐसे घपलों को तुरंत रोकने की जरूरत है।

मीना कुमारी, पटना

नकली वस्तुओं का आयात हो बंद

चीन में कई बड़ी कंपनियां अपने मशहूर ब्रांडों का उत्पादन जोर शोर से कर रही हैं, तो वहां उन्हीं ब्रांडो की नकल कर उत्पाद बनाने का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। इन नकली वस्तुओं का निर्यात अधिकांश देशों को हो रहा है, ऐसे में नकली वस्तुओं के बाजार में आने से मशहूर ब्रांडों के मूल्यों एवं उनके कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी चपेट में ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं एवं ब्रांडेड फुटवियर तथा अन्य वस्तुएं भी आएंगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चीन सरकार इन उद्योगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, तथा जिस तरह यह अनेक देशों में फैला है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन की सरकार इसके प्रति काफी नरम रुख रखती है। भारत में भी इसका आयात तेजी से बढ़ रहा है तथा हमारे देश के बंदरगाहों पर यह माल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से देश के अंदर पहुंच रहा है। ऐसे में इन बड़े ब्रांडों के साथ-साथ छोटे ब्रांडों के मूल्यों को भी खतरा पहुंच रहा है और ग्राहकों को ब्रांडेड के नाम पर नकली सामान दिया जा रहा है। सरकार को यथाशीघ्र इसकी सुध लेनी चाहिए। उसे नकली वस्तुओं के आयात तथा बंदरगाह पर तैनात भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कंपनियों एवं ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

विमलेंद्र मणि त्रिपाठी, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

एथनॉल खरीद के लिए नई निविदा जारी

पिछली निविदाओं में मिली थी खराब प्रतिक्रिया, शीरा बनाने के लिए चीनी मिलों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था गन्ना

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 11 मार्च

चीनी कंपनियों की ओर से दो बार अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने में विफल रहने के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने वर्ष 2019-20 के एथनॉल खरीद सत्र के बाकी महीनों के लिए एक बार फिर 2.53 अरब लीटर एथनॉल खरीद के लिए निविदा जारी की है। यह सत्र दिसंबर से नवंबर तक चलता है।

नई निविदा इसलिए मंगाई गई थी क्योंकि पिछले साल अगस्त में जारी 5.11 अरब लीटर एथनॉल की खरीद वाली पहली निविदा में काफी कम बोली मिली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चीनी मिलों के पास शीरा बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं था। पहली निविदा के जवाब में केवल 1.40 अरब लीटर की पेशकश की गई थी और इसे चीनी कंपनियों तथा पृथक डिस्टिलरियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

तेल विपणन कंपनियों ने अपनी आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जनवरी 2020 में एथनॉल की तीन अरब लीटर से अधिक की शेष मांग के लिए 2.53 अरब लीटर की दूसरी निविदा जारी की थी। दूसरी निविदा में भी चीनी मिलें इस पूरी मात्रा की आपूर्ति की गारंटी नहीं दे पाई थीं और उन्होंने 0.31 अरब लीटर की ही पेशकश की। इसमें से केवल 0.29 अरब लीटर के अनुबंधों को ही अंतिम रूप दिया गया था। दूसरे दौर की दूसरी निविदा के तौर पर पिछले सप्ताह एक बार फिर 2.53 अरब लीटर की यह नई निविदा लाई गई थी। हालांकि चीनी कंपनियों का कहना है कि इसमें भी कई आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बोली नहीं आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले एक साल में पर्याप्त संख्या में क्षमता नहीं जोड़ी जाएगी।

चीनी कंपनियों और पृथक डिस्टिलरियों की ओर से एथनॉल की कम आपूर्ति के कारण वर्ष 2022 तक भारत के 10 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। वर्ष 2018-19 में भारत ने लगभग पांच प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। मौजूदा रुख को देखते वर्ष 2019-20 के चालू सत्र में भी प्रदर्शन में कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा।

अनिवार्य एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में देरी से सामान्य गन्ना किसान को चीनी के दामों में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इससे भुगतान में देरी हो सकती है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों

का कहना है कि गन्ने की कम उपलब्धता के अलावा तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी की गई खरीद निविदा के लिए खराब प्रतिक्रिया मिलने के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि अनाज आधारित उत्पादकों, पृथक डिस्टिलरी और एकीकृत चीनी मिलों की एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार धीमा है।

सूत्रों ने कहा कि एथनॉल उत्पादन क्षमताएं जोड़ने के प्रस्तावों को खाद्य मंत्रालय से शीघ्रतापूर्वक मंजूरी मिलने के बावजूद एथनॉल उत्पादन क्षमताओं में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चीनी कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट के कारण केंद्र की ब्याज छूट योजना के तहत बैंक इन कंपनियों के एथनॉल विस्तार परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं देना चाहते हैं। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीनी कारोबार में पिछले नुकसान की वजह से कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट के कारण केंद्र द्वारा विस्तार परियोजना को मंजूर किए जाने के बावजूद बैंक आसान ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा एक साल में मंजूर 362 एथनॉल उत्पादन परियोजनाओं में से केवल तकरीबन 56 (लगभग 16 प्रतिशत) परियोजनाओं को बैंकों से अंतिम मंजूरी मिली है और इसमें से 37 को ही सस्ता कर्ज मिला है।

इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2019 में, जब तेल विपणन कंपनियों ने 5.11 अरब लीटर एथनॉल खरीद के लिए पहली निविदा जारी की थी, तब सभी स्रोतों से कुल एथनॉल उत्पादन क्षमता अनुमानित रूप से करीब 3.55 अरब लीटर थी। अब यह बढ़कर 3.8 अरब लीटर हो चुकी है। इस तरह इसमें करीब आठ महीने में केवल 0.25 अरब लीटर का ही इजाफा हुआ है। अगर अगले दो से तीन सालों के दौरान इन सभी 362 परियोजनाओं द्वारा निर्मित की जाने वाली क्षमताएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो एथनॉल की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 10 अरब लीटर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य छह अरब लीटर भी मौजूदा 3.8 अरब लीटर में जोड़ दिया जाएगा।

मार्च 2019 में केंद्र ने एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरी स्थापित करने वाली कंपनियों को 3,355 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी के साथ 15,000 करोड़ रुपये के आसान ऋण के पैकेज को मंजूरी दी थी।

सत्र 2019-20 की एथनॉल निविदा

- पहली निविदा में तेल विपणन कंपनियों की एथनॉल मांग : **5.11** अरब लीटर
- एथनॉल आपूर्ति को दिया गया अंतिम रूप : **1.5** अरब लीटर
- दूसरी निविदा में तेल विपणन कंपनियों की एथनॉल मांग : **2.53** अरब लीटर
- एथनॉल आपूर्ति को दिया गया अंतिम रूप : **0.31** अरब लीटर
- तीसरी *निविदा में तेल कंपनियों की एथनॉल मांग : **2.53** अरब लीटर
- नोट : पहली निविदा अगस्त 2019 में, दूसरी जनवरी 2020 में और नवीनतम निविदा मार्च 2020 की शुरुआत में जारी की गई

स्रोत : चीनी कंपनियां, *अब भी खुली हुई है निविदा

कच्चा तेल: एमसीएक्स पर मार्जिन में आई नरमी

राजेश भयानी
मुंबई, 11 मार्च

कच्चा तेल कारोबारियों को सोमवार को शुरू हुए संकट के बाद तीसरे दिन मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ा। बाजार कारोबारियों का कहना है कि बुधवार को बैंक बंद थे, लेकिन एमसीएक्स शाम के सत्र के लिए खुला था और मार्जिन में कमी की उम्मीद से कच्चे तेल की कुछ लॉन्ग पोजीशन दर्ज की गईं।

बाजार को कल कुछ राहत मिली, क्योंकि कीमतों में सुधार से उन कारोबारियों के लिए अतिरिक्त मार्जिन की जरूरत घटी थी जो नकदी संकट महसूस कर रहे थे। एमसीएक्स ने भी मार्जिन 60 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया जिससे दबाव के स्तर में कमी आने का संकेत मिलता है।

मुंबई स्थित केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'जिंस ब्रोकरों के लिए यह बेहद कठिन समय है, क्योंकि भारतीय कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह नीचे आ गईं, जो किसी एक दिन में इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। ब्रोकर मार्जिन जुटाने में व्यस्त रहे, क्योंकि मार्जिन 15 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत पर पहुंच गया था।'

मार्जिन हालांकि कमजोर हुआ है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में आज इस उम्मीद से हुई खरीदारी की मदद से सुधार दिखा कि अमेरिकी उत्पादक उत्पादन में कटौती करेंगे।

सोमवार को, जब एमसीएक्स में भारी गिरावट आई थी, नुकसान घटाने या मार्जिन कॉल पूरी करने के लिए कच्चे तेल में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा। बुधवार को, दिन का कारोबारी सत्र शाम को समाप्त हुआ और इस अवधि में कीमत गिरकर 2,335 रुपये प्रति बैरल रह गई। एक अधिकारी ने कहा कि कीमत इतनी कम नहीं बनी रहीं और तुरंत इसमें सुधार आया जिससे संकेत मिलता है कि यह गिरावट ओपन इंटरेस्ट से बड़े लॉट में कमी की वजह से आई।

शुक्रवार को कच्चा तेल अनुबंध में ओपन इंटरेस्ट 29,000 से ऊपर था, जो कल घटकर 18,449 रह गया। हालांकि माना जा रहा है कि मार्जिन चुकाने वाले और लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखने वाले कारोबारियों द्वारा ओपन इंटरेस्ट में फिर से तेजी के साथ कुछ पोजीशन जोड़े गए। मार्जिन भुगतान के बाद पोजीशन बनाए रखने में सफल रहे कारोबारियों ने मार्जिन 60 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह जाने की वजह से और पोजीशन जोड़े।

हालांकि शुक्रवार से अनुबंध सौदों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। ब्रोकर कई ग्राहकों को मौजूदा समय में बेहद उतार-चढ़ाव वाले बाजार से दूर बने रहने की सलाह दे रहे हैं।

तेल संकट

- संकट के बाद तीसरे दिन मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ा कारोबारियों को
- बुधवार को शाम के सत्र के लिए खुला था एमसीएक्स
- एमसीएक्स ने मार्जिन 60 से घटाकर 45 प्रतिशत किया

भारत से मलेशिया की चीनी खरीद में तीन गुना इजाफा

वर्ष 2020 के दौरान अब तक भारत से मलेशिया को किए जाने वाले चीनी निर्यात में पिछले साल के मुकाबले लगभग तीन गुना इजाफा हुआ है क्योंकि मलेशिया ने एक व्यापारिक विवाद की वजह से भारत को संतुष्ट करने के लिए अपनी खरीद बढ़ा दी है। इस विवाद में मलेशिया से भारत को किया जाने वाला पाम तेल निर्यात रुक गया था। कारोबार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

इस रिकॉर्ड खरीद से दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश भारत को अपने स्टॉक के जमावड़े में कमी लाने में मदद मिल सकती है जिससे भारत के घरेलू दामों में कमी आ रही है। भारत पांच सालों से मलेशिया के पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन जनवरी में पाम तेल आयात सीमित किए जाने के बाद इसमें गिरावट आ गई। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना के जवाब में यह कदम उठाया गया था।

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी ने रॉयटर्स को बताया कि मलेशिया इस साल जोरदार ढंग से भारत की कच्ची चीनी खरीद रहा है जो एक सुखद आश्चर्य की बात है। व्यापार संघ के आंकड़े बताते हैं कि मलेशिया ने इस साल भारत से 3,24,405 टन चीनी का आयात किया है, जबकि पिछले साल भारत ने करीब 1,10,000 टन और वर्ष 2008 में 3,13,406 टन का रिकॉर्ड निर्यात किया था। रीफिनिटिव इकॉन पर अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में मलेशिया ने कुल 19.5 लाख टन कच्ची चीनी का आयात किया था। वह आम तौर पर ब्राजील, थाइलैंड और फिर भारत से खरीद करता है।

एक वैश्विक कारोबारी कंपनी के मुंबई स्थित व्यापारी ने कहा कि वर्ष 2020 में मलेशिया की भारत से चीनी खरीद आसानी से 4,00,000 टन का स्तर पार कर सकती है क्योंकि अब भी कुछ खेप रास्ते में हैं। मुंबई के ही एक अन्य व्यापारी ने कहा कि मलेशिया रिफाइनरों को भारत से चीनी खरीद करने को तरजीह देने के लिए कह सकता है। यह भारत को खुश करने की कोशिश है।

जनवरी में इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश के शीर्ष चीनी रिफाइनर - एमएसएम मलेशिया होल्डिंग्स बेरहैड ने कहा था कि वह पहली तिमाही के दौरान भारत से 4.92 करोड़ डॉलर मूल्य की 1,30,000 टन कच्ची चीनी खरीदेगा। *रॉयटर्स*

मध्य प्रदेश: गहराता सियासी संकट

संदीप कुमार

मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही देर बाद भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्य सभा का उम्मीदवार बना दिया। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव 26 मार्च को होने हैं जबकि प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च को बुलाया गया है।

भाजपा में शामिल होने के बाद अपने पहले संबोधन में सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता की सेवा नहीं कर पाने के कारण वह कांग्रेस में आहत थे।

सिंधिया ने कहा, 'जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तब हमने एक सपना देखा था। लेकिन 18 महीने में वो सारे सपने बिखर गए। चाहे वो किसानों के ऋण माफ करने की बात हो, पिछले फसल का बोनस न मिलना हो। ओलावृष्टि से नष्ट फसल आदि का भी मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है।'

सिंधिया की दोनों बुआओं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंधिया को कद्दावर नेता बताते हुए उनका स्वागत किया।

फोटोः दलीप कुमार

> 'आज की कांग्रेस पार्टी वह पार्टी नहीं है जो पहले थी। पार्टी वास्तविकता से इनकार कर रही है। नई सोच, विचारधारा एवं नए नेतृत्व को कोई मान्यता नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य सुरक्षित है'
>
> **ज्योतिरादित्य सिंधिया**

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिंधिया को मिलने का समय नहीं देने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सिंधिया इक्लौते शख्स हैं जो उनके घर कभी भी आ सकते थे। राहुल ने बुधवार को ट्विटर पर अपना एक पुराना ट्वीट फिर से साझा किया जो उन्होंने दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के चयन के समय किया था।राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने का विश्वास जताते हुए दावा किया कि 22 बागी विधायकों में 13 ने कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, 'यह गलती हमसे हुई कि हम यह नहीं समझ पाए कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे। कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया। चार बार सांसद बनाया, दो बार केंद्रीय मंत्री बनाया और कार्यसमिति का सदस्य बनाया।' कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए जयपुर स्थानांतरित कर दिया है। उधर बेंगलुरू गए 22 बागी विधायकों में से 17 ने वीडियो संदेश जारी करके सिंधिया में अपनी आस्था दोहराई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने तो यह तक कहा कि वह सिंधिया के लिए कुंए में भी कूद जाएंगी।

सिंधिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया था। उनके साथ ही 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इससे प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सिंधिया को निष्कासित किया गया है। पार्टी छोड़ने की वजहों का जिक्र करते हुए सिंधिया ने कहा, 'अभी जो कांग्रेस पार्टी है, वह पहले जैसी पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी में वास्तविकता से इनकार करने के साथ-साथ नई सोच, विचारधारा एवं नए नेतृत्व को मान्यता नहीं दी जाती है। वहां (कांग्रेस) राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अलग-अलग विडंबना है। ऐसे में मैंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।'

उधर सिंधिया को शामिल किए जाने से मप्र भाजपा में भी सर फुटव्वल हो सकती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक सिंधिया को पार्टी में शामिल करने से प्रभात झा काफी नाराज हैं। पार्टी ने इस बार राज्य सभा से भी उन्हें टिकट नहीं दिया। उनका राज्य सभा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। पार्टी में नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने भी एक दूसरे खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

साल 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा के साथ विवाद होने पर सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने भी 36 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी जिसके चलते मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी जो 20 महीने चली।

दिल्ली हिंसा सुनियोजित: शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी धर्म, जाति या पार्टी से जुड़ा हो।

शाह ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के उनके कार्यक्रमों में नहीं गए और पूरे समय दिल्ली पुलिस के साथ बैठकें कर हिंसा को नियंत्रित करने की दिशा में लगे रहे। शाह ने कहा कि इस मामले में 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 2,647 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि आईटी कानून के तहत 25 मामले दर्ज किए गए हैं और 60 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की जांच चल रही है जो दंगा शुरू होने से पहले शुरू हुए और बाद में बंद हुए।

उन्होंने देश के लोगों एवं राजनीतिक दलों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि यह (जांच) पूरे देश के लिए एक सबक होगी कि दंगा करने वालों का अंजाम क्या होता है। शाह ने कहा कि दंगों में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, इस संबंध में सरकार ने एक दावा निस्तारण आयोग गठित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

अमित शाह, गृह मंत्री

- उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा के मामलों में कुल **2647** लोग हिरासत में लिए गए हैं
- शाह ने कहा ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के उनके कार्यक्रमों में नहीं गए
- वह उस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ बैठकें कर हिंसा रोकने की कोशिश में जुटे थे

लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया और उन पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को पूरे दिल्ली में नहीं फैलने देने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के कुल 203 थाने हैं और हिंसा केवल 12 थाना क्षेत्रों तक सीमित रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी हिंसा को रोकने की थी।

गृह मंत्री ने कहा, '14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी (कांग्रेस) ने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी रैली की, उसमें पार्टी की अध्यक्ष महोदया भाषण में कहती हैं कि घर से बाहर निकलो, आर-पार की लड़ाई करो, अस्तित्व का सवाल है। उनके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाओगे। यह हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाला भाषण) नहीं है क्या? इसके बाद ही 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ।'

एजेंसियां

देश-दुनिया में कोरोना का खौफ

- भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या **60** पर पहुंची
- कोरोनावायरस से संक्रमित देशों से आने वाले अंतराष्ट्रीय यात्री-जहाजों के आगमन पर **31** मार्च तक पाबंदी
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना संकट में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार इटली भी भेजेगी चिकित्सा दल
- केरल ने इटली से लौटे **45** लोगों को निगरानी में रखा
- वाहन उद्योग के संगठन सायम ने कहा कोरोनावायरस के चलते वाहन उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होगा
- ब्रिटेन की ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज के मुताबिक कोरोनावायरस के चलते दो प्रतिशत घट सकती है आर्थिक वृद्धि की रफ्तार
- ईरान में कोरोनावायरस से **63** और मरीजों की जान गई, अब तक कुल **354** लोगों की इस बीमारी से मौत
- दक्षिण कोरिया में पांच दिन में पहली बार बढ़े कोरोनावायरस के मामले
- अमेरिका ने ईरान से अपने कैदियों को रिहा करने की मांग की
- मध्य अमेरिकी देश पनामा में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला
- इटली ने कोरोनावायरस से जूझने के लिए पेश किया **25** अरब यूरो का पैकेज
- कोरोनावायरस के संक्रमण से इटली में अब तक **631** लोगों की मौत हो चुकी है
- वुहान पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कुछ फैक्ट्रियों में काम शुरु
- तुर्की और श्रीलंका में पहला मामला